STUDY IQ PUBLICATIONS

72वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा

बिहार करेंट अफेयर्स

एक वर्ष के समसामयिक घटनाक्रम – बिहार विशेष

बिहार बजट 2026-27

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

बिहार सरकार की नई नीतियां/विधेयक

विषय सूची

- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 1
- बिहार का बजट 2026-27 9
- बिहार सरकार की नई नीतियां/विधेयक 16
- बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप्स/पोर्टल 17
- आईएसएफआर रिपोर्ट 2023: बिहार 18
- सीसीईए ने बिहार में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी 19
- प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया 19
- बिहार राज्य महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस 19
- मधुबनी का जितवारपुर गांव बिहार का पहला हस्तशिल्प गांव बनने जा रहा है। 20
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया 20
- बिहार में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई 20
- बिहार को दो नए रामसर स्थल मिले। 20
- बिहार के शैलेश कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया 20
- ऑपरेशन आहट 20
- बिहार में चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की 20
- NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी सेंटर, मुजफ्फरपुर, बिहार 21
- बिहार विधानसभा के 18वें चुनाव 21
- मखाना महोत्सव 2025, पटना, बिहार में 21
- बिहार ने राष्ट्रीय स्वात चौंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदक जीते 21
- ''छोटी चिरैया'' बनी बिहार की चुनावी आइकन! 21
- प्रधानमंत्री 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' अभियान शुरू करेंगे: .. 21
- इस राज्य में हर साल सड़क हादसों में 8,873 लोगों की मौत होती है। 21
- फाइलेरिया उन्मूलन के लिए रात्रि रक्त सर्वेक्षण शुरू 22
- बिहार की अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या 22
- तीरंदाजी प्रशिक्षक जय प्रकाश को बिहार राज्य खेल पुरस्कार प्राप्त होगा 22
- बिहार में 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप हैं। 22
- बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र 22
- पटना नगर निगम की 'पिंक इनोवेशन' को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता 22
- बिहार के चार उत्पाद राष्ट्रीय डिजिटल बाजार (ई-एनएएम) में शामिल किए गए। 22
- गोगबील झील: भारत का नया (94वां) रामसर स्थल 23
- स्तन के दूध में यूरेनियम का पता लगाना 23
- भारत में मुफ्त दवा वितरण में बिहार पहले स्थान पर है। 23
- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 23
- बिहार में तीन नए रेल गलियारे 24
- डॉ. प्रेम कुमार 25
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद 25
- बिहार सरकार की युवाओं के लिए एक बड़ी पहल 25
- नीतीश कुमार ने लंदन स्थित विश्व अभिलेख पुस्तिका में अपना नाम दर्ज कराया। 25
- नागरिक सुरक्षा जिला 26
- मंत्रिमंडल की बैठक से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ 26
- 63वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चौंपियनशिप 2025 26
- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड 26
- बिहार बोर्ड को तीन अंतरराष्ट्रीय आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुए 26
- काग्यू मोनलम चेन्मो 26
- सात निश्चय-3 (सात निश्चय-3) 27
- खेल विकास योजना 27
- ऑपरेशन ''भूमि दखल देहानी'' 27
- युवा राष्ट्रीय खेल 27
- पूर्णिया में मौसम रडार परियोजना 27
- एकीकृत रोग निगरानी 28
- बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव 28
- दर्शन परिषद का 47वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। 28
- अनुकूल रॉय 28
- राज्य पर्यटन विभाग 28
- पटना उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति 28
- कैमूर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित (बिहार) 28
- छह जिलों में भूकंपीय वेधशालाएँ 29
- सौर ऊर्जा-सह-बैटरी भंडारण परियोजना 29
- न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू 29
- महारानी कमसुंदरी देवी 29
- ग्रामीण सड़कों के लिए क्यूआर कोड निगरानी 29
- रानी चाओ खुन फ्रा सिनानाथ बिलासक्ल्यानि 29
- श्रेयस बी. चंद्र 29
- काठी स्क्रिप्ट 29
- विदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ 29
- बिहार: समृद्धि यात्रा 29

- मल्टीमॉडल टर्मिनल 30
- 22 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया 30
- त्यागराजन एस.एम 30
- अर्थशिला, पटना 30
- अनाज एटीएम 30
- मिडिल स्कूल उफ्रेल 30
- बिहार सेमीकंडक्टर नीति 30
- बिहार विधानसभा का आम बजट 30
- किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता 30
- मखाना-लीची में नंबर वन, अब चावल-गेहूं पर ध्यान केंद्रित। 30
- 1.1 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र 31
- बिहार राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड 31
- खेलों के लिए प्रयास 31
- डायनासोर पार्क 31
- वैभव सूर्यवंशी 31
- सोनपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 31
- "सुकन्या जिला" पहल-समस्तीपुर 31
- डॉप्लर मौसम रडार 31
- बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित 31
- राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 31
- 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चौम्पियनशिप 31
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गांव 32
- सीवान का बेटा, बिहार का गौरव 32
- सैयद अता हसनैन 32
- नागालैंड के नए राज्यपाल 32
- औद्योगिक विकास 32
- इकबाल हसन रिशु 32
- पंखुड़ी सोनी 32
- सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) और विंड्रो प्लांट 32
- मुफ्त दवाइयों की उपलब्धता में बिहार पहले स्थान पर है 32
- जीविका दीदी की आवाज केंद्र 32
- राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 32
- बिहार का बलिराजगढ़ किला 33
- डॉ. महेंद्र झा 33
- सिद्धांत सारंग 33
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान 33
- बिहार का 114वां स्थापना दिवस 33
- 100 नए हवाई अड्डों की योजना - बिहार में 4 33
- नीतीश कुमार का इस्तीफा 34
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा 34
- वेस्टर्न सोन नहर पर सौर ऊर्जा संयंत्र 34
- सिंचाई के लिए 'आशा मॉडल' 34
- रग्बी प्रतियोगिता 34
- गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट/सर्विस अवार्ड-2026 34
- राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 34
- बिहारवन 34
- जोर शीतल महोत्सव 34
- सम्राट चौधरी बिहार के 21वें मुख्यमंत्री बने। 34
- बिहार के मुख्यमंत्री (1946-2026) 35
- मिथिला चित्रकला-महिलाओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई 35
- मिथिला की प्रमुख पद्म श्री पुरस्कार विजेता महिला चित्रकारी कलाकार 35
- वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर 36
- 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चौम्पियनशिप 2026 36
- कैमूर हिल्स में उच्च सुरक्षा वाली जेल 36
- दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर 36
- राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान (बिहार) 36
- एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) 36
- बिहार राज्य राजमार्ग चार परियोजना 36
- बिहटा (पटना) में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन 37
- लीची का डंक मारने वाला कीट - कार्य बल का गठन 37
- बिहार मंत्रिमंडल विस्तार 2026 37
- मालभोग केला 37
- भगवान महावीर स्वामी की 72 फुट ऊंची प्रतिमा 37
- प्रथम विश्व योगासन खेल चौम्पियनशिप 2026 37
- डॉ. जया भारती 38
- बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम 38
- गंगा पथ (मरीन ड्राइव) परियोजना 38
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) 38
- बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 38
- पिरपैंती ताप विद्युत परियोजना 39

वार्षिक समसामयिक घटनाक्रम - बिहार विशेष

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य के आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्थिति और विकास पथ का व्यापक और आंकड़ों पर आधारित आकलन प्रस्तुत करता है। यह बिहार की मजबूत विकास गति, क्षेत्रीय परिवर्तन और अवसंरचना, मानव विकास और समावेशी विकास पर केंद्रित नीतिगत पहलुओं को उजागर करता है।

तेजी से हो रहे जीएसडीपी विस्तार और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय से लेकर कृषि, बिजली, ई-गवर्नेंस और सामाजिक क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण सुधारों तक, जो बिहार की अर्थव्यवस्था की एक स्पष्ट मैक्रो-से-माइक्रो तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अध्याय I - बिहार की अर्थव्यवस्था: एक अवलोकन: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

- 2024-25 के नवीनतम त्वरित अनुमानों के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 8.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह 13.1 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 5,31,372 करोड़ रुपये और 9,91,997 करोड़ रुपये हो गया।
- पिछले तीन वर्षों में, बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान और स्थिर दोनों ही दरों पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर से लगातार अधिक रही है। वर्तमान दरों पर बिहार की सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि दर 2022-23 में 17.9 प्रतिशत और 2023-24 में 14.9 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि भारत की वृद्धि दर क्रमशः 14.0 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत रही। 2024-25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, बिहार की जीडीपी (वर्तमान दरों पर) वृद्धि दर 13.1 प्रतिशत और भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर, बिहार की अर्थव्यवस्था की 2024-25 में 8.6 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान है, जो भारत की 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है। ये आंकड़े बिहार को भारत के सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में शामिल करते हैं।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2024-25 के त्वरित अनुमानों से संकेत मिलता है कि बिहार में द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में स्थिर (2011-12) कीमतों पर 11.1 प्रतिशत और वर्तमान कीमतों पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र में स्थिर (2011-12) कीमतों पर 8.9 प्रतिशत और वर्तमान कीमतों पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 2024-25 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर 4.1 प्रतिशत और वर्तमान कीमतों पर 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 2020-21 और 2024-25 के बीच, स्थिर (2011-12) कीमतों पर बिहार के सकल वार्षिक लाभ मूल्य (जीएसवीए) में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि के कारण 21.1 प्रतिशत से बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.9 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत हो गई, और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 57.0 प्रतिशत से घटकर 54.8 प्रतिशत हो गई। ये बदलाव राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ते विविधीकरण को दर्शाते हैं।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2020-21 में 46,412 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 76,490 रुपये हो गई है, जो निरंतर वृद्धि का संकेत देती है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2020-21 में 30,159 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 40,973 रुपये हो गई है।
- के अनुसार **बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26**बिहार में, पटना जिले का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) सबसे अधिक रहा, उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर का स्थान रहा। वर्तमान कीमतों पर पटना का प्रति व्यक्ति जीडीपीडीपी 2,41,220 रुपये, बेगूसराय का 1,05,600 रुपये और मुंगेर का 93,921 रुपये था।
- कुल मिलाकर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक आशावादी, भविष्योन्मुखी मूल्यांकन प्रदान करता है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राज्य व्यापक आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विविधीकरण, बढ़े हुए निवेश और मानव पूंजी विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के संवर्धन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के कारण उच्च विकास पथ पर प्रगति कर रहा है।

अध्याय II - राज्य वित्त बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, बिहार की राजकोषीय प्रगति अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है, क्योंकि राज्य सरकार का कुल व्यय 2020-21 में 1.66 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय को लगातार प्राथमिकता दी है, साथ ही संयमित उधार और प्रभावी ऋण सेवा के माध्यम से राजकोषीय विवेक बनाए रखा है।
- राज्य सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2020-21 में 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 22.3 प्रतिशत हो गया, जबकि राजस्व व्यय का हिस्सा 84.2 प्रतिशत से घटकर 77.7 प्रतिशत हो गया। यह संरचनात्मक परिवर्तन दीर्घकालिक निवेश, अवसंरचना विकास और परिसंपत्ति सृजन पर सरकार के फोकस को रेखांकित करता है।
- राज्य सरकार के राजस्व खाते में प्राप्तियां 2020-21 में 1.28 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.18 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जिसमें कर राजस्व प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा। राजस्व खाते में कर प्राप्तियों का हिस्सा 70 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया, जबकि गैर-कर राजस्व पांच प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत हो गया और अनुदानों का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गया।
- पिछले पांच वर्षों में राजस्व व्यय की संरचना काफी हद तक स्थिर रही है, जिसमें सामाजिक सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक (46 प्रतिशत) है। आर्थिक सेवा क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 में 21 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 22 प्रतिशत हो गया, जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2020-21 में 33 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 32 प्रतिशत हो गया। यह वितरण कल्याणकारी विकास और उत्पादक क्षेत्रों को मजबूत करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- राज्य सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 2020-21 में 38.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 39.9 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात 61.7 प्रतिशत से घटकर 60.1 प्रतिशत हो गया है। यह प्रवृत्ति कल्याणकारी पहलों और नीति-आधारित विकास प्राथमिकताओं की ओर क्रमिक बदलाव को दर्शाती है।
- राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक व्यय लगातार बजट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा रहा है, जो 2024-25 में कुल व्यय का 67.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक व्यय 2020-21 में 1,12,122 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,89,892 करोड़ रुपये हो गया है, जो विकासोन्मुखी और कल्याणकारी व्यय पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
- केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व 2020-21 में 91,625 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,59,298 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मुख्य कारण विभाज्य कर कोष से हस्तांतरण में वृद्धि है, जो 2020-21 में 59,861 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,29,435 करोड़ रुपये हो गया। केंद्र सरकार से अनुदान सहायता 2024-25 में 29,863 करोड़ रुपये रही। साथ ही, राज्य का अपना राजस्व भी 2020-21 में 36,543 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 59,360 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें कर राजस्व का मुख्य योगदान रहा है।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का बकाया ऋण 3,74,134 करोड़ रुपये था, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 37.7 प्रतिशत है। 2024-25 के अंत में कुल बकाया ऋण में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 84.6 प्रतिशत था। कुल सार्वजनिक ऋण में से 83.8 प्रतिशत आंतरिक स्रोतों से आया था, जबकि 16.2 प्रतिशत केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित था। बाजार ऋण और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण आंतरिक ऋण के प्रमुख घटक हैं।

अध्याय III - कृषि और संबद्ध क्षेत्र

- अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी 2023-24 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का सकल राज्य मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में 23.1 प्रतिशत का योगदान रहा। इस क्षेत्र में, फसल उत्पादन का जीएसवीए में 11.5 प्रतिशत का योगदान रहा, जबकि पशुधन का योगदान 8.1 प्रतिशत रहा।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2023-24 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल, गेहूं और मक्का का योगदान 99.9 प्रतिशत था। 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.7 प्रतिशत, गेहूं का 32.1 प्रतिशत और मक्का का 27.1 प्रतिशत रहा। 2023-24 और 2024-25 के बीच चावल उत्पादन में 4.3 प्रतिशत, गेहूं उत्पादन में 7.1 प्रतिशत और मक्का उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- यह राज्य भारत में फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और लीची, मखाना और मशरूम का एक प्रमुख उत्पादक है। राज्य में कुल बागवानी उत्पादन 2023-24 में लगभग 230 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2019-20 में लगभग 206 लाख टन था, जिसमें फलों और सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक है।
- 2023-24 और 2024-25 के बीच, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, अंडे के उत्पादन में 10.0 प्रतिशत और मछली उत्पादन में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- मुख्यमंत्री समीकित चौर विकास योजना बिहार के चौर क्षेत्रों में मत्स्य पालन आधारित एकीकृत खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है। 2024-25 में, इस योजना के तहत 24.67 करोड़ रुपये के व्यय से 510.0 हेक्टेयर चौर भूमि का विकास किया गया, जो मछली पालकों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यी विकास योजना का उद्देश्य मछली के बीज उत्पादन, मछली उत्पादन और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए तालाबों, पोखरों और अन्य जल संसाधनों के सतत उपयोग को अधिकतम करना है। योजना के विभिन्न घटकों के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 में 40.95 करोड़ रुपये खर्च किए। इस व्यय का बड़ा हिस्सा, 30.35 करोड़ रुपये, तालाबों में मछली पालन के लिए अग्रिम इनपुट आपूर्ति योजना के विस्तार के लिए आवंटित किया गया था।
- बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड रियायती दरों पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य फसलों के बीज उपलब्ध करा रहा है। धान की उन किस्मों (जिनकी अवधि 10 वर्ष से कम है) के लिए 50,163 क्विंटल बीज किसानों को वितरित किए गए, जिनकी अवधि 10 वर्ष से अधिक है, और 10,478.67 क्विंटल बीज 2024-25 में वितरित किए गए। गेहूं उत्पादन के लिए, दोनों किस्मों को मिलाकर 3,57,552 क्विंटल बीज 2024-25 में किसानों को वितरित किए गए।
- एक नई पहल के तहत, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ने सभी जिलों के किसानों को सशुल्क घर-घर बीज पहुंचाने की व्यवस्था की है। बीज की घर-घर डिलीवरी शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। कुल मिलाकर, 2024-25 में 4,73,618 किसानों को 1,17,064.55 क्विंटल बीज वितरित किए गए।
- राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कुल 75 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए 82.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत 2024-25 में 104.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं (केंद्र सरकार का हिस्सा: 62.50 करोड़ रुपये; राज्य सरकार का हिस्सा: 41.67 करोड़ रुपये)।
- कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा 2020-21 में 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 14.9 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान कृषि के लिए 3,47,310 बिजली कनेक्शन प्रदान किए, जिनमें से 85.0 प्रतिशत कनेक्शन पिछले दो वर्षों में जारी किए गए। कृषि के लिए बिजली सब्सिडी 2022-23 और 2024-25 के बीच 99.3 प्रतिशत बढ़कर 4,056.99 करोड़ रुपये हो गई।
- 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों की संख्या 2023-24 की तुलना में 16.3 प्रतिशत बढ़ी। वितरित ऋण की कुल राशि 2023-24 में 7,080.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 9,399.24 करोड़ रुपये हो गई, जो 32.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

- 2024–25 में सिंचाई पर कुल व्यय 2,729.83 करोड़ रुपये था, जिसमें से 74.3 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था। 2023–24 और 2024–25 के बीच सिंचाई पर कुल व्यय में 63.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक व्यय में यह वृद्धि प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के पर्याप्त विस्तार में परिलक्षित होती है।
- सात निश्चय चरण–2 पहल के तहत, 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' कार्यक्रम को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए तैयार किया गया है। लगभग छह महीनों में, 29,952 योजनाओं की पहचान की गई, जिनमें 6,504 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 7,79,201 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- जैविक कॉरिडोर योजना के लिए राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन हेतु 104.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 24,500 रुपये की सब्सिडी तीन किस्तों में दी जाती है: पहली किस्त 11,500 रुपये की, और दूसरी और तीसरी किस्त 6,500 रुपये की। यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि के लिए प्रदान की जाती है।
- खरीफ 2024 के दौरान अनियमित मानसून और सामान्य से कम वर्षा के मद्देनजर, डीजल सब्सिडी योजना के तहत 150.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इस योजना से सभी 38 जिलों के किसानों को लाभ मिला। यह सब्सिडी प्रति किसान आठ एकड़ तक की सिंचाई के लिए देय थी। इस योजना के तहत 2024–25 में 3.28 लाख किसानों के खातों में 61.21 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
- 2024–25 कृषि वर्ष में, किसानों को खरीफ ऋतु में बाढ़ और रबी ऋतु में ओलावृष्टि और/या बेमौसम बारिश दोनों का सामना करना पड़ा। 2024–25 खरीफ ऋतु की बाढ़ में 2.62 लाख किसानों को कुल 169. 98 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला, जबकि रबी फसल के नुकसान से प्रभावित 0.12 लाख किसानों को 5.28 करोड़ रुपये का मुआवजा प्राप्त हुआ। 2025–26 खरीफ ऋतु में, बाढ़ से प्रभावित 2.41 लाख किसानों को 113.50 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला।
- बिहार में जलवायु–अनुकूल कृषि कार्यक्रम (सीआरए–2) के लिए 30 जिलों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन काल 2020–21 से 2024–25 तक है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 238.49 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

अध्याय IV – उद्यम क्षेत्र: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

- बिहार के द्वितीयक क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में उतार–चढ़ाव देखा गया है। महामारी के कारण 2020–21 में तीव्र संकुचन के बाद, इसने 2021–22 में पुन: उत्थापन प्राप्त किया और खनन, उपयोगिता और निर्माण के नेतृत्व में 2022–23 में मजबूत वृद्धि दर्ज की। 2023–24 में खनन में गिरावट आई, लेकिन अन्य उपक्षेत्रों ने इस क्षेत्र को 12 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने में मदद की। 2024–25 के लिए त्वरित अनुमान 8.6 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि का संकेत देते हैं, जो मुख्य रूप से उपयोगिता और निर्माण के कारण होगी, जबकि विनिर्माण में मामूली वृद्धि होगी।
- 2019–20 और 2023–24 के बीच, बिहार की औद्योगिक पूंजी सघनता और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति अचल पूंजी दोगुनी होकर 25.9 लाख रुपये हो गई, जबकि श्रम उत्पादकता 2023–24 में 10 लाख रुपये तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय स्तर का 93.5 प्रतिशत है।
- 2024–25 में, COMFED ने अपने खुदरा आउटलेट्स की संख्या 31,529 से बढ़ाकर 34,795 कर बाजार में अपनी उपस्थिति को 10.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत किया। अपनी ''लोकल टू ग्लोबल'' पहल के तहत, COMFED ने अमेरिका और कनाडा को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस खेप में अमेरिका को 36,50,714 रुपये मूल्य का 5 मीट्रिक टन गाय का घी और 8,30,000 रुपये मूल्य का 0.5 मीट्रिक टन मखाना भेजा गया, जबकि कनाडा को 8,23,669 रुपये मूल्य के लगभग 5 मीट्रिक टन गुलाब जामुन के डिब्बे भेजे गए।
- निवेश के मोर्चे पर, राज्य को 4,353 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 3,539 को 2016–17 से 2025–26 (सितंबर 2025 तक) के बीच प्रथम चरण की मंजूरी मिल गई। कुल प्रस्तावित निवेश 1.11 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें 2016–23 और 2024–25 के बीच महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ। इन प्रस्तावों में से 1,187 प्रस्ताव वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के चरण तक पहुंचे, जिनमें 13,693.4 करोड़ रुपये का निवेश शामिल था।
- इसके अतिरिक्त, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत 956 औद्योगिक इकाइयां चालू हुईं, जिनमें 10,635.90 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 42,999 लोगों को रोजगार मिला। निवेशकों को सहयोग देने के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 के बीच 994.55 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे अधिक इकाइयां चालू हैं, जो निवेशकों की मजबूत रुचि और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन को दर्शाती हैं।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत, 2023–24 और 2024–25 के बीच प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 4,64,453 से बढ़कर 7,74,567 हो गई। उदाहरण के लिए, जाति और जनसांख्यिकी–विशिष्ट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के घटकों के तहत, युवा उद्यमियों के आवेदन 71,924 से बढ़कर 1,51,384 हो गए, जबकि लाभार्थियों की संख्या केवल 1,532 से बढ़कर 2,169 हुई।
- बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत, 2024–25 के अंत तक 1,239 स्टार्टअप को प्रमाणित किया गया और राज्य सरकार ने सीड फंडिंग के रूप में 32.18 करोड़ रुपये वितरित किए। इस तेजी का असर 2024–25 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रमाणित स्टार्टअप की संख्या दोनों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में दिखाई देता है।
- 2023–24 में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2023 में 5.47 लाख से बढ़कर 2024 में 7.37 लाख हो गई। 2024–25 में पर्यटन क्षेत्र के लिए स्वीकृत बजट 841.95 करोड़ रुपये था, जो 2023–24 के आवंटन से ढाई गुना अधिक था। 2025–26 के लिए बजट और बढ़कर 1,097.25 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024–25 की तुलना में 30.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2024–25 के दौरान वास्तविक व्यय 778.02 करोड़ रुपये रहा, जो 92.7 प्रतिशत की उच्च उपयोग दर को दर्शाता है।
- 28 पर्यावरण–पर्यटन स्थलों पर, 2024–25 में कुल पर्यटकों की संख्या 37.8 लाख तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.0 प्रतिशत

अधिक है। 2024-25 में, पर्यावरण-पर्यटन और पार्क विकास के लिए कुल व्यय 100.00 करोड़ रुपये था।

अध्याय V - श्रम, रोजगार और कौशल: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में 61.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए थे, जिनमें से 50.3 प्रतिशत स्वयं-रोजगार में कार्यरत थे। दिहाड़ी मजदूर पुरुष श्रमिकों का दूसरा सबसे बड़ा समूह थे, जिनमें से 28.5 प्रतिशत दिहाड़ी पर काम करते थे।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 15,145 दावों के लिए 63.73 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। 2023-24 और 2024-25 के बीच, दावों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई, जबकि अनुदान राशि में ढाई गुना वृद्धि हुई।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2024-25 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या 508.5 हजार थी और लाभार्थियों की संख्या 100.54 हजार थी। इसी वर्ष कुल उपकर संग्रह 768.63 करोड़ रुपये रहा, जिसमें से बोर्ड ने 536.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जो 70 प्रतिशत की उपयोगिता दर को दर्शाता है।
- बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 16 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के लिए राज्य सरकार ने 802.47 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से सितंबर 2025 तक 14,68,792 श्रमिकों को 734.40 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके थे।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 4,94,249 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें से 4,29,015 पद वर्ष 2023-24 में विज्ञापित किए गए थे, जो इस अवधि के दौरान विज्ञापित सभी पदों का 87 प्रतिशत है। हालांकि, वर्ष 2023-24 में विज्ञापित पदों के लिए चयन प्रक्रिया दो वर्षों, 2023-24 और 2024-25 तक चली। वर्ष 2023-24 और 2024-25 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 2,23,153 और 1,12,173 थी।
- 2023-24 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 11,330 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। 2025-26 में (30 सितंबर, 2025 तक) 6,722 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। पिछले साढ़े चार वर्षों में (2021-22 से सितंबर 2025 तक), आयोग ने 20,499 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए और उनमें से 18,249 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2025-26 में (सितंबर 2025 तक) केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड ने 45,590 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिनमें से 21,391 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। चयनित 21,391 उम्मीदवारों में से 52 प्रतिशत महिलाएं थीं और आठ व्यक्ति ट्रांसजेंडर थे।
- बिहार तकनीकी सेवा आयोग तकनीकी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है। 2024-25 में 8,215 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जबकि 2025-26 में (सितंबर 2025 तक) बिहार में विभिन्न तकनीकी सेवाओं के लिए 8,673 उम्मीदवारों का चयन हुआ।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2024-25 में आरएसईटीआई ने हाल के वर्षों में अपना सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवधि के दौरान कुल 41,901 व्यक्तियों के लिए 1,323 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2023-24 और 2024-25 के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में 36.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्रशिक्षुओं की संख्या में 37.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रशिक्षित लोगों में से 76.7 प्रतिशत को 2024-25 में रोजगार प्राप्त हुआ।
- दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत, सितंबर 2025 तक विभिन्न व्यवसायों में 84,558 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और डीडीयू-जीकेवाई और रोशनी परियोजनाओं के तहत विभिन्न संस्थानों में 46,196 उम्मीदवारों को रोजगार मिला है। 2024-25 में, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन पर कुल व्यय 45.27 करोड़ रुपये रहा।
- पिछले पांच वर्षों में, 1,782.99 हजार आवेदकों में से लगभग 1,585.02 हजार आवेदकों को सफलतापूर्वक पासपोर्ट प्राप्त हुए। अकेले तीन जिलों (सिवान, गोपालगंज और पटना) में 2024-25 में पासपोर्ट आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों का 31 प्रतिशत हिस्सा था। 2021-22 से 2024-25 तक बिहार में पासपोर्ट आवेदनों में 39.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में पासपोर्ट जारी किए गए पासपोर्टों में 38.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अध्याय VI - भौतिक अवसंरचना

- उच्च आर्थिक विकास को गति देने के लिए निर्मित एक मजबूत सड़क नेटवर्क के आधार पर, राज्य अब आधुनिकीकरण और सामाजिक समानता पर केंद्रित दोहरी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। यह रोडमैप केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में अगली पीढ़ी के एक्सप्रेसवे और समर्पित कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता देता है, साथ ही साथ एक सघन ग्रामीण सड़क नेटवर्क के माध्यम से समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करता है। 2014-2026 के दौरान प्रत्येक गांव को जोड़ने के लिए 70,560 करोड़ रुपये का निवेश करके, राज्य ने ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजारों से सफलतापूर्वक जोड़ा है और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में सुधार किया है, जिससे स्थानीय उत्पादन और क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों के बीच की खाई को पाटा जा सका है।
- परिवहन के अन्य साधनों में, सड़क परिवहन आसान, सुविधाजनक, सुलभ, किफायती है और घर-घर तक पहुंच प्रदान करता है। सड़क परिवहन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास चालकों में से एक है। पिछले डेढ़ दशक में इसने 13.4 प्रतिशत की उच्च वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, परिवहन मोटर वाहनों के उच्चतम पंजीकरण के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में पांचवें स्थान पर है, जबकि गैर-परिवहन मोटर वाहनों के मामले में वर्ष 2024 के दौरान राज्य सातवें स्थान पर है। बिहार में कुल 13.95 लाख मोटर वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो वर्ष 2024 में देश के पंजीकृत मोटर वाहनों का 5.3 प्रतिशत है।
- जीएसवीए के एयरवेज सेक्टर का कारोबार 2011-12 से 2024-25 के दौरान 15 गुना बढ़कर 31 करोड़ रुपये से 453 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार बिहार के प्रमुख शहरों में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए

प्रतिबद्ध है। चार हवाई अड्डे (पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया) चालू हैं। इनके अलावा, 13 अन्य हवाई अड्डे विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

- इसी अवधि के दौरान जीएसवीए के जल परिवहन क्षेत्र में वार्षिक 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों में बिहार के कालूघाट में एक इंटरमॉडल टर्मिनल, 21 सामुदायिक जेट्टी और एक त्वरित पोंटून खोलने की व्यवस्था का निर्माण शामिल है। भविष्य की योजना का एक परिवर्तनकारी तत्व पटना में शहरी जल मेट्रो परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपये है।
- 2020 से 2025 के बीच, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड ने स्थिर वित्तीय प्रदर्शन बनाए रखा, जिसका औसत वार्षिक कारोबार 55.35 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 17 करोड़ रुपये रहा। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने पिछले दशक में राज्य के बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार किया है, जिसमें 15,583 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश से 882 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने किफायती और कल्याणकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है, जिसने पिछले पांच वर्षों में 10.07 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करके और 514.52 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करके अपनी मजबूत परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है।
- बिहार राज्य भवन निर्माण निगम ने कुल 2556 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनमें 7396 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। शेष परियोजनाएं विभिन्न चरणों में पूरी होने वाली हैं। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने लगातार परिचालन लाभ अर्जित किया है, जो इसके सुदृढ़ तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। यह सफलता वास्तुकला डिजाइन, संरचनात्मक अभियांत्रिकी और गुणवत्ता नियंत्रण में अंतर्निहित विशेषज्ञता के कारण संभव हुई है, जो समय पर परियोजना पूर्णता सुनिश्चित करती है और बाहरी आउटसोर्सिंग पर निर्भरता को कम करती है।

अध्याय VII – ई-गवर्नेंस: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र बिहार के विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है, और राज्य सरकार सुदृढ़ बुनियादी ढांचा तैयार करने और डिजिटल प्रौद्योगिकी दक्षता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्तमान में, एक परिवार के दो सदस्यों के पास मोबाइल फोन है और एक सदस्य के पास इंटरनेट की सुविधा है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल पहुंच से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों और सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- राज्य सरकार ने नवंबर 2025 में 'बिहार एआई मिशन' को अपनाया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास और शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस मिशन का लक्ष्य एआई-आधारित सेवाओं को बढ़ावा देकर, कार्यबल को प्रशिक्षित करके और उद्योगों को एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके बिहार को एआई अपनाने में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
- बढ़ते साइबर अपराधों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से निपटने के लिए राज्य ने कई ई-गवर्नेंस कार्यक्रम विकसित किए हैं। सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म को अपनाने और उपयोग करने में बिहार का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। मई 2025 में एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित प्रगति डैशबोर्ड में बिहार ने 87.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उच्च स्थान हासिल किया। यह अंक सीसीटीएनएस परियोजना के विभिन्न परिचालन मापदंडों में राज्य के सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है, जो अपराध और अपराधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक, डेटा-आधारित प्रणाली की ओर पुलिस बल के प्रभावी परिवर्तन की पुष्टि करता है।
- बिहार में तत्काल जन सहायता के लिए संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, डायल 112, एक एकीकृत समाधान है जिसमें वर्तमान में 1833 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन, 1556 एम्बुलेंस, 784 अग्निशमन वाहन और 61 राजमार्ग गश्ती वाहन शामिल हैं। यह एकीकृत नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि आपातकाल की प्रकृति चाहे जो भी हो-पुलिस, चिकित्सा या आग-सटीक स्थान का उपयोग करके निकटतम और सबसे उपयुक्त सहायता शीघ्रता से संकट स्थल पर भेजी जाए।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, जून 2025 तक राज्य में 7,637 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1,237 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर पुलिस स्टेशन, पुलिस अधीक्षक (साइबर) के निर्देशन में 'साइबर प्रहार' नामक एक विशेष अभियान सक्रिय रूप से चला रहे हैं।
- बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी को डिजिटल बनाने के लिए ''ई-कोर्ट'' पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर विवादों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से निपटारा करना है।
- भूमि विवादों के प्रभावी निपटान, निगरानी और नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गृह विभाग ने भू-समाधान पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल ने मामलों के समाधान में उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शित की है: प्राप्त कुल 87,203 आवेदनों में से 69,958 मामलों का अंतिम निपटान और 6,764 मामलों का प्रारंभिक निपटान हो चुका है। लंबित मामलों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।
- राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में CFMS 2.0 को लागू किया। इस उन्नत संस्करण में आधुनिक API-आधारित आर्किटेक्चर शामिल है, जो मौजूदा प्रक्रियाओं को समर्थन और बेहतर बनाने के साथ-साथ बजट प्रबंधन, ई-बिलिंग, कोषागार प्रबंधन, लेखा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में नई कार्यक्षमताओं को भी जोड़ता है। CFMS 2.0 सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और RBI की ई-कुबेर प्रणाली के साथ भी एकीकृत है, जिससे SNA SPARSH के माध्यम से समय पर बिलों की प्रोसेसिंग आसान हो जाती है।

अध्याय VIII – विद्युत क्षेत्र

- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011-12 में 134 किलोवाट-घंटे से बढ़कर 2024-25 में 374 किलोवाट-घंटे हो गई है, जो बढ़ती पहुंच और मांग को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र में मजबूत वित्तीय और परिचालन पुनरुद्धार हुआ है, जिसमें एटी एंड सी घाटा 2013-14 में 42.99 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 15.54 प्रतिशत हो गया है, जो पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना के

मानकों से बेहतर प्रदर्शन है। इस प्रगति को दर्शाते हुए, राज्य की वितरण कंपनियों ने निरंतर लाभ दर्ज करना शुरू कर दिया है, जिनकी आय 2022–23 में 215 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024–25 तक 1959 करोड़ रुपये हो गई है, जो मजबूत राजकोषीय स्थिरता और क्षेत्रीय लचीलेपन को इंगित करता है।

- बिजली अवसंरचना में बिहार का निरंतर निवेश विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 2005 में 45 से बढ़कर 2025 तक 175 हो गई है, जिनमें से 16 का निर्माण कार्य जारी है। इसी अवधि में पारेषण नेटवर्क 5,000 सीकेएम से बढ़कर 21,165 सीकेएम हो गया है, साथ ही 2,369 सीकेएम का अतिरिक्त नेटवर्क निर्माणाधीन है।
- अनुमान के अनुसार, घरेलू उपभोक्ता कुल बिजली मांग का लगभग आधा हिस्सा यानी 47.78 प्रतिशत खपत करेंगे। कृषि क्षेत्र लगभग 16. 79 प्रतिशत खपत करेगा, जबकि शेष 35.43 प्रतिशत खपत औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों जैसे गैर-घरेलू उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी।
- बिहार की कुल विद्युत क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा (7,743 मेगावाट) शामिल है। इसके बाद, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका योगदान 1,922 मेगावाट है। जलविद्युत का योगदान 1,356 मेगावाट और पवन ऊर्जा का योगदान 699 मेगावाट है। गन्ने की खोई और बायोमास से ऊर्जा मिश्रण में मामूली 44 मेगावाट का योगदान होता है। तापीय ऊर्जा उत्पादन आपूर्ति का मुख्य आधार बना हुआ है, हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर, राज्य का विद्युत पोर्टफोलियो विविध और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर संतुलित प्रगति को दर्शाता है।
- बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, बिहार अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विस्तार और प्रणाली उन्नयन के माध्यम से अपने पारेषण नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 2012–13 में 80 से बढ़कर 2025–26 में 175 हो गई है, जो 6.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। इसी अवधि में, रूपांतरण क्षमता में भी 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जो 15,170 मेगावाट से बढ़कर 37,090 मेगावाट हो गई है, जिसमें 7.5 प्रतिशत की सीएजीआर है, जो पारेषण अवसंरचना में निरंतर निवेश को रेखांकित करता है।
- राज्य की वितरण कंपनियों ने नए सबस्टेशनों, उन्नत हाई टेंशन/लो टेंशन लाइनों और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिचालन सुधारों के माध्यम से वितरण नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। बिजली कनेक्शन 2011–12 में 38 लाख से बढ़कर 2024–25 में 21 लाख से अधिक हो गए हैं, जो लगभग 5.5 गुना वृद्धि दर्शाता है और औसत वार्षिक वृद्धि दर 17 प्रतिशत है। घरेलू उपभोक्ताओं का दबदबा अभी भी 88.5 प्रतिशत है, हालांकि वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के कारण कृषि कनेक्शनों में 2018–19 से 289 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- बिजली की उपलब्धता के लिए की गई खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2020–21 में 32,071 एमयू से बढ़कर 2024–25 में 51,192 एमयू हो गई है–चार वर्षों में 19,121 एमयू की वृद्धि। उच्च खपत से राजस्व प्राप्ति में मजबूती आई है, जिससे क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। लागत कवरेज 2020–21 में 88.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 106 प्रतिशत हो गया है, जो पूर्ण लागत वसूली और राजकोषीय स्थिरता की ओर एक बदलाव का संकेत है।

अध्याय IX – ग्रामीण विकास: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26

- 2024–25 में 175.1 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए, जो 2022–23 की तुलना में 4.8 प्रतिशत अधिक थे। बिहार में, जॉब कार्ड धारकों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 2024–25 में 19.9 प्रतिशत था, जबकि 2023–23 में यह 17.9 प्रतिशत था।
- एमजीएनआरईजीएस के तहत, 2024–25 में ग्रामीण संपर्क कार्यों की संख्या में 9.07 प्रतिशत, सूक्ष्म सिंचाई कार्यों की संख्या में 8.02 प्रतिशत और जल संरक्षण एवं जल संचयन कार्यों की संख्या में 6.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा–2 शुरू किया। एक नए सर्वेक्षण में पात्र श्रेणियों में 1,23,346 भूमिहीन परिवारों की पहचान की गई, जिनमें से 39,405 परिवारों को आवास भूमि आवंटित की जा चुकी है। सरकार ने समावेशी विकास और ग्रामीण बेघरता के व्यापक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, 2024–25 में आवास भूमि वितरण के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, 2025 में राज्य में 49,434 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आउटलेट संचालित थे, जो 2023 की तुलना में मामूली वृद्धि दर्शाते हैं। खाद्यान्न आवंटन और उठान में वर्षों से मामूली वृद्धि देखी गई है; गेहूं और चावल का कुल आवंटन 2020–21 में 5,411.9 हजार टन से बढ़कर 2024–25 में 5,434.3 हजार टन हो गया।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का व्यय 2021–22 में 7,251.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024–25 में 8,391.48 करोड़ रुपये हो गया, जो 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर संसाधनों के बेहतर आवंटन और मजबूत वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करती है।
- राज्य सरकार ग्राम कचहरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर निवेश कर रही है। 2021–22 और 2024–25 के बीच, 1,30,868 दीवानी मामलों में से 1,22,612 का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, और 1,09,118 आपराधिक मामलों में से 1,02,377 का निपटारा किया गया, जो 2024–25 में क्रमशः 93.7 प्रतिशत और 93.8 प्रतिशत की प्रभावशाली निपटारे दर को दर्शाता है। सचिवों और न्याय मित्रों के मानदेय के लिए 161.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए; इसके अलावा, 2025–26 में सचिवों और न्याय मित्रों के लिए 201.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- बिहार में 8,053 ग्राम पंचायतों को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 2,339 भवन पूरे हो चुके हैं। 2025-26 के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 763.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से 599.13 करोड़ रुपये राज्य योजना के तहत प्रदान किए गए थे।

अध्याय X – शहरी विकास: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

- 30 शहरों में जल निकासी योजनाएं लागू की गई हैं। जल निकासी योजना के तहत कुल 2,923.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से 2024-25 तक 171.75 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसी प्रकार, 'नाला निर्माण' मद के तहत 2017 से 2024 के बीच कुल 3,618.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस योजना के लागू होने से बिहार के 260 नगर निकायों में स्थित निचले इलाकों में रहने वाले 15,73,160 लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
- सात निश्चय-2/आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत 'वृद्ध शांति गृह योजना' के पहले चरण में, पटना को छोड़कर 31 जिलों में प्रमुख नदी घाटों या जिला मुख्यालयों पर 'वृद्ध गृह' बनाने की अनुमति दी गई। सितंबर 2025 तक परियोजना की अनुमानित लागत 388.97 करोड़ रुपये थी।
- मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत, उचित जल निकासी व्यवस्था के साथ चौड़ी, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण के साथ-साथ पार्क, घाट, श्मशान घाट और अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान, राज्य सरकार ने 1,201.83 करोड़ रुपये की 1,012 योजनाओं को मंजूरी दी। वर्ष 2025-26 के लिए, राज्य सरकार ने 1,587 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 830.01 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- अटल शहरी कायाकल्प और परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत, राज्य सरकार ने 24.98 लाख घरों में पाइप से नल का पानी उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत, राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में विभिन्न नगर निकायों में 125 जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए 66.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना – शहरी के पांच घटक हैं: सामुदायिक नेतृत्व वाली संस्था विकास (सीएलआईडी), वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास (एफआईईडी), सामाजिक अवसंरचना, अभिसरण और नवाचार, और विशेष परियोजनाएं (एसआईएसपी)। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए पटना को चुना है और 2025-26 के लिए 100.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 2,64,604 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 1,82,630 परिवारों के लिए 1,82,630 आवासों का निर्माण हो चुका है, शेष आवासों को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की कुल लागत 7,292.08 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3,969.00 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 1,323.00 करोड़ रुपये है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत, सितंबर 2025 तक 3,89,226 आवेदन प्राप्त हुए और 1,53,790 घरों को मंजूरी दी गई। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 3,844.75 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 2,306.85 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 1,537.90 करोड़ रुपये है।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2024-25 में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने मुख्य रूप से सीवरेज नेटवर्क और एकीकृत एवं कुशल जल निकासी प्रणालियों, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी शामिल हैं, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 1,210.00 करोड़ रुपये थी।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में, दो कॉरिडोर पर काम पूरा करने के लिए कुल 13,925.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है: पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (दानपुर से पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक) और उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (पटना रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान और पीएमसीएच/पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होते हुए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक)। कुल ट्रैक की लंबाई 32.50 किमी है, जिसमें 13.91 किमी एलिवेटेड और 18.59 किमी अंडरग्राउंड सेक्शन शामिल हैं, और कुल 24 प्रस्तावित स्टेशन हैं।
- 2024-25 में, शहरी विकास और आवास विभाग के लिए कुल बजट आवंटन 8,274.10 करोड़ रुपये था, और कुल व्यय 1,411.82 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप उपयोग दर 68.5 प्रतिशत रही।
- पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि हुई है। 2020-21 में कुल संपत्ति कर संग्रह 191.10 करोड़ रुपये था, जो 11.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। 2024-25 तक संपत्ति कर संग्रह बढ़कर 407.54 करोड़ रुपये हो गया, जो 17.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

अध्याय XI – वित्तीय संस्थान

- बिहार में वित्तीय संस्थानों का महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण हुआ है, जिसमें भौतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना शामिल है। इस बदलाव से बैंकों को परिचालन लागत कम रखते हुए बिहार के दूरदराज के गांवों सहित व्यापक आबादी तक पहुंचने में मदद मिली है।
- जहां एक ओर बैंक की शाखाओं में लगातार स्थिर गति से वृद्धि हो रही है, जिससे राज्य का मूलभूत बैंकिंग नेटवर्क मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) का तेजी से विस्तार हुआ है, जो ग्रामीण और पहले से वंचित क्षेत्रों में अधिक गहन वित्तीय समावेशन का संकेत देता है।
- ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) राज्य में बैंकिंग सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी की नींव बनकर उभरे हैं, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कम लागत पर व्यापक पहुंच वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। बिहार में सीएसपी की संख्या 2021 में 31,095 से बढ़कर 2025 में 53,041 हो गई है, और इस अवधि के दौरान प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या में 261 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये रुझान डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। वाणिज्यिक बैंकों ने राज्य में इस परिवर्तन को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

- हालांकि बिहार का बैंकिंग नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित है, और 31 मार्च, 2025 तक इसकी 3,747 ग्रामीण शाखाएं थीं, लेकिन इसकी हिस्सेदारी 31 मार्च, 2021 के 48.6 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2025 तक 45.1 प्रतिशत हो गई है। यह भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित विस्तार और अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में बढ़ती मांग को दर्शाता है। अर्ध-शहरी शाखाओं की संख्या 31 मार्च, 2021 के 2,327 से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 2,716 हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान शहरी शाखाओं की संख्या 1,615 से बढ़कर 1,841 हो गई।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक बिहार के बैंकों में कुल 5.69 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि और 3.04 लाख करोड़ रुपये का ऋण दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा (सीडी) अनुपात 53.5 प्रतिशत रहा। बिहार में ऋण-जीएसडीपी अनुपात पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है, जो 2020-21 में 30.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 37.9 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ता रुझान दर्शाता है कि ऋण की उपलब्धता राज्य की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।
- बिहार में बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत पिछले पांच वर्षों में उल्लेखनीय रूप से घटा है, जो 2020-21 में 11.8 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 7.6 प्रतिशत हो गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों ने अपने एनपीए को 2020-21 में 10.2 प्रतिशत से सुधार कर 2024-25 में 6.0 प्रतिशत तक कम कर लिया है। राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने भी प्रगति की है, जहां एनपीए 28.1 प्रतिशत से घटकर 21.4 प्रतिशत हो गया है।

अध्याय XII – मानव विकास

- राज्य ने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो समावेशी आर्थिक विकास को रेखांकित करती है। पिछले 19 वर्षों में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, पहले दशक में पाँच गुना से अधिक और 2005-06 से 2024-25 के बीच पंद्रह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्रमशः 14.8 गुना और 13.2 गुना। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति सामाजिक सेवाओं पर व्यय और प्रति व्यक्ति विकास व्यय में नौ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- बिहार में 2019-23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष थी। 2009-2013 की तुलना में पुरुषों और महिलाओं दोनों की जीवन प्रत्याशा में 1.6 वर्ष की वृद्धि हुई है। 2019-2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा में 1.6 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 1.3 वर्ष की वृद्धि हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2017 और 2023 के बीच बिहार में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 12 अंकों की कमी आई है, जो 35 से घटकर 23 हो गई है।
- सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए, राज्य ने हाल ही में सरकारी अस्पतालों में कई परिचालन सुधार किए हैं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की औसत मासिक संख्या 2019 में 9517 से बढ़कर 2024 में 11900 हो गई, जो 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसी तरह, बाह्य रोगी विभाग में आने वाले मरीजों की संख्या में भी मामूली सुधार हुआ है, जो 2019-20 में प्रतिदिन 312 से बढ़कर 2024-25 में 388 हो गई है, यानी 1.2 गुना वृद्धि।
- बिहार में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो 2004-06 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 312 मौतों से घटकर 2021-23 में 104 रह गई है-यानी 208 अंकों की कमी। 2020-21 और 2024-25 के बीच, बिहार में जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या 15.77 लाख से बढ़कर 16.17 लाख हो गई, जो 2.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2024-25 में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कुल नामांकन 159.22 लाख था, जिनमें से 80. 87 लाख लड़के और 78.35 लाख लड़कियां थीं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन क्रमशः 27.54 लाख और 20.33 लाख था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में भी सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। सभी श्रेणियों के छात्रों में लैंगिक अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं दूसरी ओर, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में 2021-22 और 2024-25 के बीच 13.56 प्रतिशत अंकों की भारी गिरावट आई है। गौरतलब है कि इस अवधि के दौरान लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट लड़कों की तुलना में कहीं अधिक रही है।
- राज्य की पिंक बस पहल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया – इन छह जिलों में सुरक्षित, भरोसेमंद और केवल महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराती है। 100 सीएनजी से चलने वाली पिंक बसों का बेड़ा महिला यात्रियों, विशेष रूप से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती यात्रा प्रदान करता है।

अध्याय XIII – बाल विकास

- बिहार में बाल बजट तैयार करना 2013-14 से शुरू हुआ। पिछले सात वर्षों में बाल बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है। 2017-18 से 2023-24 तक बच्चों पर होने वाला व्यय 17.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2017-18 में 3,437 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 9,271 रुपये हो गया, यानी 2.7 गुना वृद्धि।
- बिहार में आंगनवाड़ी सेवाओं में निवेश लगातार बढ़ाया गया है, क्योंकि यह शिशु और मातृ पोषण के लिए इनके महत्व को पहचानता है। आंगनवाड़ी सेवाओं का बजट 2019-20 में 1,735.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2,648.47 करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग 9.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पोषण संबंधी विशिष्ट आवंटन 1,791.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,756. 13 करोड़ रुपये हो गया है, जो प्रति वर्ष 6.2 प्रतिशत की वृद्धि है।
- बिहार सरकार एमजीएनआरईजीएस के तहत अपनी 8,053 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में एक खेल का मैदान बना रही है, ताकि ग्रामीण युवाओं, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, के लिए खेलों तक पहुंच का विस्तार किया जा सके। भूमि की उपलब्धता के आधार पर तीन प्रकार के मैदान – बड़े, मध्यम और छोटे – बनाए जाएंगे, जिनकी निर्माण लागत 8.28

लाख रुपये से 9.94 लाख रुपये तक होगी और इनमें कई खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

- बिहार का मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम वार्षिक ''सुरक्षित शनिवार'' गतिविधियों, सुरक्षा केंद्रित विद्यालय विकास योजनाओं और पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल में आपदा प्रबंधन के एकीकरण के माध्यम से आपदा-प्रतिरोधी शिक्षण वातावरण को मजबूत बनाता है। 2025 में, 4,363 विद्यालय शिक्षकों और 1,005 मदरसा शिक्षकों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिस पर क्रमशः 2.62 करोड़ रुपये और 0.45 करोड़ रुपये का प्रशिक्षण व्यय हुआ।

अध्याय XIV – पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन

- गंगा नदी उपजाऊ मैदानों को दो भागों में बांटती है, जिन्हें एक दर्जन से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नदियों से पानी मिलता है। उपजाऊ दोमट मिट्टी होने के बावजूद, बिहार की भौगोलिक स्थिति इसे बाढ़, सूखा और भूकंपीय गतिविधियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। 2011 से 2025 के बीच, राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 992.4 मिमी थी, जबकि औसत वार्षिक तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस था। जलवायु परिवर्तन का गरीबों और कृषि क्षेत्र पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी उन्नत राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के माध्यम से अनुकूलन को प्राथमिकता दी है। परिणामस्वरूप, पर्यावरण संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए समर्पित सतत विकास प्रयासों से राज्य के हरित आवरण का सफलतापूर्वक विस्तार हो रहा है।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वानिकी और लकड़ी कटाई क्षेत्र राज्य की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आजीविका प्रदान करता है। 2011-12 और 2024-25 के बीच, बिहार के वानिकी और लकड़ी कटाई क्षेत्र ने वर्तमान कीमतों पर 10.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) हासिल की। इस अवधि के दौरान कुल मूल्य 4187 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,139 करोड़ रुपये हो गया। 2024-25 तक, इस क्षेत्र का कृषि सकल वन उत्पाद (जीएसवीए) में लगभग 7.0 प्रतिशत और राज्य के कुल सकल वन उत्पाद (जीएसवीए) में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान रहा।
- जलवायु वित्तपोषण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में, बिहार ने अपनी हरित बजट पहल के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को संस्थागत रूप दिया है। जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए समर्पित व्यय में चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 3308 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 16,880 करोड़ रुपये हो गया है।
- 2011 से बिहार के पारिस्थितिक पदचिह्न में लगातार वृद्धि देखी गई है। वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 9214 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 तक 9903 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो 689 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। राज्य ने एक दशक में अपने उच्चतम स्तर के हरित आवरण को प्राप्त करने में निरंतर प्रगति की है। इस अवधि के दौरान राज्य का कुल वन क्षेत्र 6,845 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7532 वर्ग किलोमीटर हो गया। विशेष रूप से, अत्यंत सघन वन (VDF) – जो उच्चतम गुणवत्ता का आवरण है – में उल्लेखनीय आनुपातिक वृद्धि देखी गई, जो 231 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 387 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो मुख्य संरक्षित क्षेत्रों के भीतर सफल संरक्षण को दर्शाता है।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत, कृषि-वानिकी पहलों और जीविका दीदियों और स्थानीय किसानों के साथ साझेदारी का लाभ उठाते हुए, राज्य ने 246 नर्सरियों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है जो सालाना लगभग 10 करोड़ पौधे पैदा करने में सक्षम हैं।
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) 23 जिलों में स्थित 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। पटना में 6 केंद्र, मुजफ्फरपुर और गया में 3-3 केंद्र और भागलपुर में 2 केंद्र हैं। सभी केंद्र सीपीसीबी सर्वर के माध्यम से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और बीएसपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। बीएसपीसीबी शेष 15 जिलों में भी अपनी वास्तविक समय निगरानी सुविधा का विस्तार करने की योजना बना रहा है।
- बीएसपीसीबी गंगा नदी की 34 स्थानों पर पाक्षिक निगरानी और इसकी सहायक नदियों और तालाबों का 70 स्थानों पर मासिक मूल्यांकन करता है। बोर्ड औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से निकलने वाले सीवेज की भी निगरानी करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड द्वारा विभिन्न स्रोतों से कुल 2937 जल, अपशिष्ट और सीवेज के नमूने एकत्र किए गए।
- गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित बिहार राज्य गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों के साथ-साथ फल्गु, पुनपुन, सकारी और चानन नदियों से सिंचित है। 2024-25 तक, बिहार के सतही जल अवसंरचना में 968 नहरें, 14,927 ट्यूबवेल, 654 टैंक (जिनमें आहार-पाइन प्रणाली, तालाब और चेक डैम शामिल हैं) और 26 जलाशय शामिल हैं, जो जल प्रबंधन और उपयोग के लिए एक ठोस आधार को दर्शाते हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा लक्षित 604 योजनाओं में से 597 पूरी हो चुकी हैं, जिससे 118,578 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बहाल हो गई है। इसके अतिरिक्त, 774 और योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 745 पूरी हो चुकी हैं, जिससे 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन या बहाली हुई है।
- लगभग सभी जिलों को बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा और आग जैसी बड़ी आपदाओं का खतरा है, कुछ क्षेत्रों में तो एक साथ कई आपदाएँ आती हैं, जो राज्य की वास्तविक बहु-आपदा स्थिति को दर्शाती हैं। 2024-25 के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए 1530.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम प्रबंधन के लिए विशेष दिशानिर्देश भी जारी किए गए।

बिहार का बजट 2026-27

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा **3** फरवरी, **2026** को प्रस्तुत किया गया बिहार का वित्त वर्ष **2026-27** का बजट राज्य के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। **₹3,47,589.76** करोड़ के कुल परिव्यय के साथ,

यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग **₹30,694** करोड़ (लगभग **10%**) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

विषय: डिजिटल सशक्तिकरण और औद्योगिक पुनरुत्थान के माध्यम से नव-निर्माण

कुल व्यय: ₹3,47,589.76 करोड़

वित्तीय लक्ष्य: जीएसडीपी में **14.9%** की वृद्धि

अध्याय 1

बिहार बजट **2026-27** का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक ''मैक्रो-इकोनॉमिक ओवरव्यू और राजकोषीय रणनीति'' है, राज्य को उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आधारभूत रोडमैप का काम करता है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत इस अध्याय में एक साहसिक राजकोषीय संरचना की रूपरेखा दी गई है, जिसे ''सात निश्चय-**3**'' (सात संकल्प-**3**) के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है।

1. **आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पाद/वृद्धि दर (जीएसडी) अनुमान:** अध्याय **1** का आधार राज्य की उल्लेखनीय आर्थिक मजबूती है। वित्तीय वर्ष **2026-27** के लिए, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान कीमतों पर **₹13.1** लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
   - विकास दर: राज्य में 15% की विकास दर का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत विकास दर के 10% के अनुमान से काफी अधिक है।
   - आर्थिक कारक: यह वृद्धि सार्वजनिक निवेश, घरेलू विनिर्माण और कृषि आधुनिकीकरण पर केंद्रित रणनीतिक ''त्रिपक्षीय'' रणनीति से प्रेरित है।
2. **बजटीय व्यय और संरचना:** कुल बजट का आकार रिकॉर्ड तोड़ **₹3,47,589.76** करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग **₹30,694** करोड़ की वृद्धि है। व्यय को रणनीतिक रूप से इस प्रकार विभाजित किया गया है ताकि चल रही प्रतिबद्धताओं और भविष्य की संपत्तियों के बीच संतुलन बना रहे।
   - राजस्व व्यय: अनुमानित ₹2,84,133.92 करोड़ (बजट का लगभग 81.7%), जिसमें वेतन (₹96,128.50 करोड़), पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल हैं।
   - **पूंजीगत व्यय:** ₹63,455.84 करोड़ (बजट का 18.26%) का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है, और इसका ध्यान सड़कों, पुलों और अस्पतालों जैसी दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है।
   - **योजना बनाम स्थापना:** विकासोन्मुखी ''योजना व्यय'' ₹1,22,155.42 करोड़ है।
3. **वित्तीय स्वास्थ्य और एफआरबीएम अनुपालन:** अध्याय **1** पिछले अस्थिर वित्तीय वर्ष के बाद राजकोषीय विवेक की ओर लौटने पर जोर देता है।
   - **राजकोषीय घाटा:** घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.99% से 3.0% (₹39,112 करोड़) के बीच रखा गया है, जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अनिवार्य 3% की सीमा का सख्ती से पालन करता है।
   - **राजस्व अधिशेष:** राज्य को ₹1,143.19 करोड़ (जीएसडीपी का 0.1%) का अधिशेष बनाए रखने की उम्मीद है, जो इस बात का संकेत है कि राजस्व प्राप्तियां दैनिक संचालन के लिए उधार लेने की आवश्यकता के बिना राजस्व व्यय को पूरी तरह से कवर करेंगी।
   - **बकाया ऋण:** यद्यपि 34% पर ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात चिंता का विषय बना हुआ है, सरकार की रणनीति ''ऋण-आधारित विकास'' पर केंद्रित है, जहां उधार को विशेष रूप से पूंजी-निर्माण परियोजनाओं में लगाया जाता है।
4. **राजस्व प्राप्ति की गतिशीलता:** इस भारी भरकम व्यय की फंडिंग केंद्रीय समर्थन और आंतरिक दक्षता में सुधार के मिश्रण पर निर्भर करती है:
   - **केंद्रीय हस्तांतरण:** बिहार केंद्र पर काफी हद तक निर्भर है, जिसमें ₹2,10,074.12 करोड़ (राजस्व का 74%) केंद्रीय करों और अनुदानों से आता है।
   - **राज्य का अपना राजस्व:** राज्य का लक्ष्य अपने स्वयं के कर और गैर-कर संसाधनों के माध्यम से ₹75,203 करोड़ जुटाना है, जो स्थानीय कर प्रशासन और जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार का संकेत है।
5. **''सात निश्चय-3'' विजन:** अंत में, यह अध्याय सभी वित्तीय निर्णयों के लिए मार्गदर्शक दर्शन के रूप में सात निश्चय-**3 (2025-2030)** ढांचे का परिचय देता है। इस वित्तीय चक्र के लिए निर्धारित प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं:
   - **रोजगार सृजन:** 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना।
   - **उत्पादकता:** संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से क्षमता को प्रदर्शन में परिवर्तित करना।
   - **समावेशिता:** विकेंद्रीकृत बजट के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय को संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो।

अध्याय 2

बिहार बजट **2026-27** के अध्याय **2** का शीर्षक है 'सात निश्चय-**3**: विकसित बिहार का खाका **(2025-2030)**'। यह अध्याय बजट का राजनीतिक और विकासात्मक केंद्र है, जिसमें सात प्रमुख संकल्पों की रूपरेखा दी गई है, जो यह निर्धारित करते हैं कि **3,47,589.76** करोड़ रुपये के इस आवंटन का उपयोग **2030** तक राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बदलने के लिए कैसे किया जाएगा।

1. **दृष्टिकोण: ''ट्रिपल टारगेट'':** इस अध्याय की शुरुआत अगले पांच वर्षों के लिए तीन व्यापक लक्ष्यों को स्थापित करने से होती है:
   - **1 करोड़ नौकरियों का सृजन:** दस मिलियन रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
   - **प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना:** औद्योगीकरण के माध्यम से औसत आय को 2024-25 के ₹76,490 के स्तर से काफी उच्च स्तर तक बढ़ाना।

– **महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता:** 1.56 करोड़ महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता।

2. **सात मुख्य संकल्प:** प्रत्येक संकल्प एक उप-अध्याय के रूप में कार्य करता है जिसमें विशिष्ट विभागीय जनादेश और वित्त पोषण होता है:

संकल्प 1: दोहरा रोजगार – दोहरी आय

सरकार ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग स्थापित किया है। सभी **534** ब्लॉकों में कौशल केंद्रों के लिए 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि युवाओं को आधुनिक उद्योग की जरूरतों के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

संकल्प 2: समृद्ध उद्योग – मजबूत बिहार

इस संकल्प से बिहार का कृषि प्रधान समाज औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होगा। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- औद्योगिक क्लस्टर: गया औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) का चरण-2 विकास।
- विशेष पार्क: पटना में एक रक्षा गलियारा, एक फार्मास्युटिकल पार्क और एक फिनटेक सिटी की स्थापना।
- पुनरुद्धार: बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और स्थानीय विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक समर्पित मिशन।

संकल्प 3: कृषि में प्रगति

ग्रामीण संपदा को बढ़ावा देने के लिए, बजट में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष **₹3,000** मिलेंगे। केंद्र सरकार की सहायता के साथ मिलाकर, बिहार के किसानों को कुल ₹9,000 वार्षिक राशि प्राप्त होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ''उपज से अधिक आय'' है, जिसके तहत उच्च मूल्य वाली फसलों और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

संकल्प 4: उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य

68,216 करोड़ रुपये के विशाल आवंटन के साथ, यह संकल्प मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर केंद्रित है। यह अनिवार्य करता है:

- **मॉडल स्कूल:** प्रत्येक पंचायत में एक उच्च तकनीक से लैस ''मॉडल स्कूल'' की स्थापना करना।
- **उच्च शिक्षा:** बढ़ते कॉलेज नेटवर्क के प्रबंधन के लिए एक अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन करना।

संकल्प 5: सुलभ स्वास्थ्य सेवा – सुरक्षित जीवन

स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। जिला अस्पतालों को सुपर-स्पेशियलिटी केंद्रों में अपग्रेड किया जा रहा है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अब विशेष सेवाएं प्रदान करेंगे। बजट में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन संयंत्रों के रखरखाव के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

संकल्प 6: मजबूत नींव – आधुनिक विस्तार

यह संकल्प भौतिक संपर्क और ''नए युग की अर्थव्यवस्था'' के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है:

- **एक्सप्रेसवे:** राज्य को पार करने वाले पांच नए एक्सप्रेसवे के लिए धन राशि।
- **डिजिटल बिहार:** घरों तक फाइबर पहुंचाने का विस्तार करना और सरकारी और निजी छतों पर सौर पैनल लगाना।

संकल्प 7: जीवन की सुगमता और सभी के लिए सम्मान

अंतिम संकल्प का उद्देश्य सामाजिक गरिमा को सुनिश्चित करना है। इसमें **2,666** नए ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण शामिल है, जिनमें स्थानीय अधिकारियों के लिए आवास भी होंगे ताकि सरकार की उपस्थिति हर व्यक्ति के घर तक सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, इसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कल्याण के लिए विशेष रूप से **₹7,724** करोड़ आवंटित किए गए हैं।

3. **अध्याय 2 की वित्तीय कार्यप्रणाली:** इन संकल्पों को मात्र कागजी वादे न बनाकर, बजट में इन सात स्तंभों के वित्तपोषण हेतु **₹1,22,155** करोड़ (कुल बजट का लगभग **35%**) विशेष रूप से ''योजना व्यय'' के रूप में आवंटित किए गए हैं। इसे एक आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क **(OOMF)** द्वारा समर्थित किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का हिसाब-किताब मापने योग्य लक्ष्यों जैसे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या या निर्मित एक्सप्रेसवे की किलोमीटर संख्या के आधार पर रखा जाए।

अध्याय 3

बिहार बजट **2026-27** का अध्याय **3**, जिसका शीर्षक ''शिक्षा और मानव पूंजी विकास'' है, राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा क्षेत्रीय निवेश है। **₹68,216** करोड़ के अभूतपूर्व आवंटन के साथ, जो कुल बजट का लगभग **19.63%** है, यह अध्याय सात निश्चय-**3** की परिकल्पना के तहत बिहार को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

1. **संरचनात्मक पुनर्गठन और वित्तीय व्यय:** बजट में विभिन्न शिक्षण चरणों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोहरे विभाग की संरचना का परिचय दिया गया है:
   – **स्कूल शिक्षा विभाग:** प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए **₹60,204** करोड़ (कुल बजट का 17.32%) का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करता है।
   – **उच्च शिक्षा विभाग:** विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ₹8,012 करोड़ (2.31%) आवंटित किए गए।
2. **प्राथमिक स्तंभ: ''आदर्श विद्यालय'' पहल:** अध्याय **3** का मुख्य उद्देश्य राज्य भर की प्रत्येक पंचायत में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करना है। ये विद्यालय शहरी और ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर को कम करने के लिए बनाए गए हैं, और इसके लिए वे निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे:
   – स्मार्ट कक्षाओं और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित मानकीकृत उच्च-तकनीकी अवसंरचना।
   – मौजूदा प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए ''उत्कृष्टता केंद्र'' दृष्टिकोण अपनाना, उन्हें उन्नत बनाना ताकि वे अपने-अपने जिलों के अन्य स्कूलों के लिए मानदंड के रूप में कार्य कर सकें।
3. **उच्च शिक्षा का विस्तार: ''हर ब्लॉक के लिए एक डिग्री कॉलेज'':** सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने और बुनियादी डिग्री के लिए

छात्रों के पलायन को रोकने के लिए, बजट में उन सभी ब्लॉकों में एक डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान है जहां वर्तमान में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसके पूरक के रूप में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों में ''विश्वविद्यालय टाउनशिप'' की स्थापना, ताकि अकादमिक अनुसंधान को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
- दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास।

4. **कौशल विकास: हब-एंड-स्पोक मॉडल:** अध्याय 3 में हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से पारंपरिक डिग्री से हटकर ''रोजगार के लिए तैयार'' कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
   - **कौशल केंद्र:** जिला स्तर पर उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित बड़े पैमाने के प्रशिक्षण केंद्र।
   - **स्पोक्स:** ब्लॉक स्तर पर छोटी प्रशिक्षण इकाइयाँ जो बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और जिला केंद्रों से जुड़ी होती हैं।
   - छात्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने हेतु माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
5. **शिक्षक सहायता और गुणवत्ता आश्वासन:** शिक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानव संसाधन विकास के लिए आरक्षित है:
   - **भर्ती और प्रतिधारण:** इष्टतम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए पिछले वर्षों में शुरू किए गए बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती अभियानों के लिए निरंतर वित्त पोषण।
   - **डिजिटल प्रशिक्षण:** शिक्षकों के लिए अनिवार्य डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नए स्मार्ट क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
6. **सीखने में सामाजिक समानता:** सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बजट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
   - **छात्रवृत्ति की निरंतरता:** माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट को रोकने के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना (यूनिफॉर्म योजना) के लिए बढ़ी हुई धनराशि।
   - **विशेष समूहों के लिए समर्थन:** 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण केंद्रों के लिए प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण।

अध्याय 3 के प्रमुख आंकड़ों का सारांश

अवयव	आवंटन	लक्ष्य
कुल शिक्षा बजट	₹68,216 करोड़	कुल बजट का 19.63%
स्कूली शिक्षा	₹60,204 करोड़	प्रत्येक पंचायत में आदर्श विद्यालय
उच्च शिक्षा	₹8,012 करोड़	हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज
कौशल लक्ष्य	1 करोड़ नौकरियों का हिस्सा	हब-एंड-स्पोक प्रशिक्षण केंद्र

अध्याय 4

बिहार बजट 2026-27 का अध्याय 4, जिसका शीर्षक ''कृषि, ग्रामीण समृद्धि और किसान कल्याण'' है, राज्य की कृषि पद्धति को ''निर्वाह'' से ''अधिशेष और लाभ'' की ओर ले जाने पर केंद्रित है। सात निश्चय-3 की परिकल्पना के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में, यह अध्याय ग्रामीण बिहार के आधुनिकीकरण और कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए बनाई गई वित्तीय व्यवस्थाओं और योजनाओं का विस्तृत वर्णन करता है।

1. **प्रत्यक्ष आय सहायता: नव किसान अनुदान:** अध्याय 4 में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का शुभारंभ है।
   - **राज्य का योगदान:** बिहार सरकार राज्य के सभी पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹3,000 प्रदान करेगी।
   - **एकीकृत सहायता:** यह अनुदान केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना (₹6,000/वर्ष) के पूरक के रूप में कार्य करता है, जिससे बिहार के किसानों को मिलने वाला कुल वार्षिक प्रत्यक्ष लाभ ₹9,000 हो जाता है।
   - **उद्देश्य:** इस कदम का उद्देश्य बीज और उर्वरक खरीदने के लिए तत्काल तरलता प्रदान करना है, जिससे उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम हो सके।
2. **विविधीकरण और उच्च मूल्य वाली कृषि:** अध्याय 4 जलवायु जोखिमों और बाजार की अस्थिरता से बचाव के लिए फसल विविधीकरण की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
   - **बागवानी और पुष्पकृषि:** मखाना, लीची और सुगंधित तेलों की खेती के लिए विशेष सब्सिडी आवंटित की जाती है, जहां बिहार को वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है।
   - **जैविक गलियारे:** गंगा के दोनों किनारों पर जैविक खेती के समूहों का विस्तार, किसानों को प्रीमियम राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए समर्पित ब्रांडिंग और प्रमाणन केंद्रों द्वारा समर्थित।
   - **चीनी उद्योग का पुनरुद्धार:** बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़े अभियान की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती को औद्योगिक इथेनॉल उत्पादन के साथ एकीकृत करना है।
3. **सिंचाई और जल प्रबंधन:** ''हर खेत के लिए पानी'' सुनिश्चित करने के लिए, बजट में जल संसाधन विभाग के लिए महत्वपूर्ण धनराशि का प्रावधान किया गया है।
   - **लघु सिंचाई:** सिंचाई की लागत को कम करने के लिए चेक-डैम और सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल को प्राथमिकता देना।
   - **बाढ़ नियंत्रण:** कृषि को बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना के साथ एकीकृत करना, यह सुनिश्चित करना कि बेहतर जल निकासी और गाद प्रबंधन के माध्यम से निचले इलाकों (ताल भूमि) की उत्पादकता बनी रहे।
4. **ग्रामीण अवसंरचना और सहकारी समितियों की क्षमता:** यह अध्याय विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ''जीवन की सुगमता'' पर जोर देता है।

- **पंचायत भवन:** 2,666 नए ग्राम पंचायत भवनों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें एकीकृत सेवा केंद्रों के रूप में डिजाइन किया गया है जहां किसान सरकारी योजनाओं और तकनीकी सलाह का लाभ उठा सकते हैं।
- **सहकारी विपणन:** आधुनिक भंडारण सुविधाओं और कोल्ड चेन को शामिल करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को मजबूत बनाना, जिससे छोटे पैमाने के किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोका जा सके।

5. **संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन और मत्स्य पालन:** पशुधन को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मानते हुए, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
   - **दुग्ध उत्पादन का विस्तार:** लघु स्तर की दुग्ध इकाइयों की स्थापना और उन्नत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए सब्सिडी।
   - **मत्स्य पालन:** बिहार को मीठे पानी की मछली का एक प्रमुख निर्यातक बनाने के लिए राज्य के विशाल आर्द्रभूमि (चौर) में ''नीली क्रांति'' पहलों को बढ़ावा देना।

अध्याय 4 की मुख्य बातों का सारांश

पहल	विशेषता	प्रभाव लक्ष्य
किसान सम्मान निधि	प्रति वर्ष ₹3,000 अतिरिक्त	प्रति किसान कुल ₹9,000 प्रति वर्ष
औद्योगिक संपर्क	चीनी मिलों का पुनरुद्धार	स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना
कौशल केंद्र	कृषि-उद्यमिता	कृषि उद्यमियों का सृजन
ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित	2,666 पंचायत भवन	अंतिम-मील सेवा वितरण

अध्याय 5

बिहार बजट **2026-27** का अध्याय **5**, जिसका शीर्षक ''स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उत्कृष्टता'' है, सात निश्चय-3 के जनादेश के तहत बुनियादी प्रावधानों से उन्नत और सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है। **21,000** करोड़ रुपये से अधिक के कुल क्षेत्रीय आवंटन (विभागीय और पूंजीगत व्यय सहित) के साथ, यह अध्याय विकेंद्रीकृत सुपर-स्पेशलिटी नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए ''सुरक्षित जीवन'' के निर्माण पर केंद्रित है।

1. **विकेंद्रीकरण: जिला स्तर पर सुपर-स्पेशलिटी:** अध्याय 5 की मुख्य रणनीति विशेष देखभाल के विकेंद्रीकरण द्वारा पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे पटना स्थित अस्पतालों पर बोझ को कम करना है।
   - **जिला अस्पतालों का उन्नयन:** सरकार ने जिला अस्पतालों को सुपर-स्पेशलिटी केंद्रों में परिवर्तित करने का आदेश दिया है। इसमें प्रत्येक जिले में कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी (डायलिसिस) और ऑन्कोलॉजी के लिए समर्पित विंग की स्थापना शामिल है।
   - **पीएमसीएच का पुनर्विकास:** बजट में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) के विश्व स्तरीय पुनर्विकास के लिए निरंतर धन उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्देश्य इसे बिस्तर क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाना है।
2. **''बायोफार्मा शक्ति'' पहल:** इस अध्याय की एक प्रमुख विशेषता बायोफार्मा शक्ति (स्वास्थ्य और ज्ञान-आधारित तकनीकी नवाचार के लिए प्रणालियाँ) पहल का शुभारंभ है।
   - **क्लिनिकल ट्रायल सेंटर:** बजट में राज्य भर में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटरों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार को चिकित्सा अनुसंधान और दवा विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
   - **फार्मा पार्क:** उद्योग विभाग के समन्वय से, अध्याय 5 में जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष फार्मास्युटिकल पार्क के निर्माण की रूपरेखा दी गई है।
3. **चिकित्सा शिक्षा का विस्तार:** स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए, बजट में ''प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज'' योजना को गति दी गई है।
   - **नए संस्थान:** चार नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र शुरू करने और छह अन्य कॉलेजों के लिए सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए धन राशि स्वीकृत कर दी गई है।
   - **संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर:** संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (पैरामेडिक्स, प्रयोगशाला तकनीशियन और रेडियोलॉजिस्ट) को विशेष संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित करने पर नया जोर दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारियों की कमी के कारण आधुनिक नैदानिक उपकरण बेकार न पड़े रहें।
4. **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच):** यह बजट महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा जाल को मजबूत करता है:
   - **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग:** सभी उपविभागीय अस्पतालों में 100 बिस्तरों वाले समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निर्माण।
   - **टीकाकरण और पोषण:** 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने और एक नए स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए आंगनवाड़ी नेटवर्क के साथ स्वास्थ्य सेवा का एकीकरण।
5. **डिजिटल स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाएं**
   - **हेल्थ डिजिटल स्टैक:** सभी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) का कार्यान्वयन, जिससे प्राथमिक केंद्रों और सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों के बीच निर्बाध रेफरल संभव हो सके।
   - **डायल 102 का विस्तार:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कॉल आने के 20 मिनट के भीतर आपातकालीन देखभाल उपलब्ध कराने के लिए ''एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट'' (एएलएस) एम्बुलेंस के बेड़े को बढ़ाना।

अध्याय 5 की मुख्य बातों का सारांश

पहल	विशेषता	लक्ष्य
सुपर-स्पेशलिटी केंद्र	जिला स्तरीय विशिष्ट शाखाएँ	पटना के अस्पतालों में भीड़ कम करना

पहल	विशेषता	लक्ष्य
बायोफार्मा शक्ति	1,000 नैदानिक परीक्षण केंद्र	चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना
मेडिकल कॉलेज	10 से अधिक नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं	''एक कॉलेज, एक जिला''
डिजिटल हेल्थ स्टैक	इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड	निर्बाध रोगी ट्रैकिंग

अध्याय 6

बिहार बजट **2026-27** का अध्याय **6**, जिसका शीर्षक ''बुनियादी ढांचा, उद्योग और शहरी परिवर्तन'' है, सात निश्चय-3 की परिकल्पना का मूल आधार है। आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, यह अध्याय बताता है कि राज्य अपने **₹39,377** करोड़ के पूंजीगत व्यय का उपयोग प्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार और अधिक रहने योग्य शहरों के निर्माण के लिए कैसे करेगा।

1. **औद्योगिक पुनर्जागरण:** अध्याय **6** का एक प्रमुख उद्देश्य बिहार को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक केंद्र में बदलना है, जिसका लक्ष्य **2030** तक **1** करोड़ रोजगार सृजित करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
   - **औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी):** बजट में गया आईएमसी के चरण-2 को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, जो अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर एक प्रमुख केंद्र है और इसे भारी विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स फर्मों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
   - **क्षेत्र-विशिष्ट पार्क:** उच्च मूल्य वाली सेवाओं और विशेष विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए पटना के पास एक फार्मा पार्क और एक फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं।
   - **चीनी मिलों का पुनरुद्धार:** उत्तरी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थायी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और उन्हें इथेनॉल उत्पादन के साथ एकीकृत करने के लिए एक समर्पित मिशन को वित्त पोषित किया गया है।
2. **कनेक्टिविटी: एक्सप्रेसवे युग:** माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, बजट में सड़क अवसंरचना में भारी वृद्धि की घोषणा की गई है।
   - **नए एक्सप्रेसवे:** सरकार ने पांच नए एक्सप्रेसवे बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इनका उद्देश्य प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के बीच यात्रा के समय को कम करना और राज्य के रसद नेटवर्क की रीढ़ बनना है।
   - **ग्रामीण-शहरी संपर्क:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निरंतर निवेश यह सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक गलियारे दूरस्थतम गांवों से सुलभ हों, जिससे ग्रामीण श्रम को औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जा सके।
3. **शहरीकरण और ''जीवन की सुगमता'':** बिहार की शहरी आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, शहरी विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी) को ₹15,237 करोड़ का पर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ है।
   - **भावी शहरों का विकास:** बजट में 19 नगर निगमों, 89 परिषदों और 156 नगर पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें नगर आर्थिक क्षेत्र मानचित्रण के माध्यम से इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाने पर जोर दिया गया है।
   - **जल निकासी और स्वच्छता:** चिरस्थायी जलभराव से निपटने के लिए, ₹3,560 करोड़ की लागत से 38 प्रमुख तूफानी जल निकासी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ अब सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करती हैं।
   - **स्मार्ट सिटी:** बजट रिपोर्ट में पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में स्वीकृत 122 परियोजनाओं में से 101 परियोजनाओं के पूरा होने की जानकारी दी गई है, जिनमें एकीकृत यातायात प्रबंधन और डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
4. **ऊर्जा और हरित अवसंरचना**
   - **सतत गतिशीलता:** हरित ऊर्जा की ओर एक बड़ा बदलाव सार्वजनिक बसों को सीएनजी और विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने से जुड़ा है।
   - **इलेक्ट्रिक वाहनों का अवसंरचना:** बजट में राज्य भर में 2,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए धनराशि आवंटित की गई है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
   - **विद्युत क्षेत्र:** 18,737 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, औद्योगिक समूहों को 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने और साथ ही सौर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अध्याय 6 की मुख्य बातों का सारांश

सेक्टर	प्रमुख परियोजना/आवंटन	लक्ष्य
उद्योग	गया आईएमसी फेज-2	विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजित करना
परिवहन	5 नए एक्सप्रेसवे	राज्यव्यापी तीव्र कनेक्टिविटी
शहरीकरण	यूएचडी के लिए ₹15,237 करोड़	रहने योग्य शहर और जल निकासी व्यवस्था
ऊर्जा	2,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	हरित परिवहन की ओर संक्रमण

अध्याय 7

बिहार बजट **2026-27** के अध्याय **7** का शीर्षक है ''सभी के लिए सम्मान – सुगम जीवन: सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता''। यह अध्याय सात निश्चय-3 रोडमैप (**2025-2030**) के अंतिम स्तंभ को शामिल करता है, जो सामाजिक गरिमा, आपदा प्रतिरोध क्षमता और जलवायु-अनुकूल विकास के माध्यम से ''जीवन की सुगमता'' पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी मिले।

1. **सामाजिक कल्याण और मानवीय गरिमा:** इस अध्याय का मुख्य फोकस समाज कल्याण विभाग पर है, जिसे ₹8,379.07 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है।
   - पेंशन योजनाएं: बजट में 90 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित किया गया है।
   - दिव्यांग समावेशन: व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ''डिग्निटी मिशन'' के लिए समर्पित है, जो दिव्यांगजनों (विशेष रूप से सक्षम) को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता, सहायक उपकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
   - **ट्रांसजेंडर कल्याण:** पिछली पहलों को आगे बढ़ाते हुए, अध्याय 7 में ट्रांसजेंडर समुदाय को आश्रय और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ''गरिमा गृह'' (सम्मानजनक घर) के लिए विशिष्ट धनराशि आवंटित की गई है।
2. **महिलाओं के नेतृत्व में विकास और सशक्तिकरण:** राज्य के प्रमुख फोकस को जारी रखते हुए, यह अध्याय ''आसान जीवन'' में महिलाओं के कल्याण को एकीकृत करता है।
   - **मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना:** 2025 के अंत में शुरू की गई इस योजना को स्वयं सहायता समूहों की 1.56 करोड़ महिलाओं को ₹10,000 का प्रारंभिक अनुदान प्रदान करने के लिए निरंतर वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिससे लघु स्तर की आजीविका को बढ़ावा मिलता है।
   - **महिलाओं की सुरक्षा:** सार्वजनिक सुरक्षा और आवागमन में सुगमता लाने के लिए बिहार भर के सभी 1,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने और ''महिला सहायता डेस्क'' के विस्तार के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
3. **पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन:** पहली बार, अध्याय 7 पर्यावरण संरक्षण को ''सभी के लिए सम्मान'' के एक मुख्य घटक के रूप में महत्व देता है, यह मानते हुए कि जलवायु परिवर्तन से गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
   - **हरित बिहार मिशन:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ₹1,075.40 करोड़ प्राप्त हुए। इस बजट का लक्ष्य राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाना है।
   - **नवीकरणीय ऊर्जा:** कम उपयोगिता लागत के साथ ''आसान जीवन'' को बढ़ावा देने के लिए, बजट कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडी वाले ''सौर ऋण'' के माध्यम से सौर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को प्रोत्साहित करता है।
   - 4. **आपदा प्रबंधन और लचीलापन:** बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ और लू को देखते हुए, बजट में गरिमापूर्ण जीवन के लिए सुरक्षा को एक पूर्व शर्त के रूप में प्राथमिकता दी गई है।
   - **आपदा प्रबंधन आवंटन:** प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और समुदाय-आधारित आपदा प्रतिक्रिया टीमों के लिए ₹479.27 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

- **लू से बचाव:** शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में ''कूल रूफ'' पहल शुरू करने और गर्मियों के चरम समय के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल कियोस्क (पियाउ) का विस्तार करने के लिए धनराशि आवंटित की जाती है।

5. **अल्पसंख्यक कल्याण और समावेशन:** अध्याय 7 में लक्षित शैक्षिक और अवसंरचनात्मक सहायता के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर भी चर्चा की गई है।
   - **छात्रावास और कौशल केंद्र:** सभी 38 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण पूरा किया गया है।
   - **वक्फ संपत्ति विकास:** सार्वजनिक उपयोगिता स्थलों के रूप में कार्य करने के लिए वक्फ भूमि पर बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों और विवाह हॉलों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना।

अध्याय 7 की मुख्य बातों का सारांश

सेक्टर	आवंटन/लक्ष्य	मुख्य उद्देश्य
समाज कल्याण	₹8,379.07 करोड़	सामाजिक गरिमा और सुरक्षा पेंशन
पर्यावरण	₹1,075.40 करोड़	5 करोड़ पौधे और हरियाली
महिला सहायता	1.56 करोड़ लाभार्थी	स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार
आपदा प्रबंधन	₹479.27 करोड़	बाढ़/गर्मी की लहरों के प्रति लचीलापन

अध्याय 8

बिहार बजट **2026-27** का अंतिम अध्याय, जिसका शीर्षक ''सुशासन और पुलिस आधुनिकीकरण'' है, कानून के शासन को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता में सुधार पर केंद्रित है। गृह विभाग और आंतरिक सुरक्षा के लिए **20,000** करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ, यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सात निश्चय-3 की परिकल्पना के तहत ''समृद्ध बिहार'' के लिए ''सुरक्षित बिहार'' एक पूर्व शर्त है।

1. **पुलिस आधुनिकीकरण और विशेष शाखाएँ:** सरकार ने राज्य पुलिस बल के तकनीकी और संरचनात्मक उन्नयन को प्राथमिकता दी है।
   - जिला पुलिसिंग: जिला पुलिस अभियानों के लिए विशेष रूप से 9,455 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कर्मियों की उपस्थिति बढ़ाना है।
   - विशेष इकाइयाँ: उभरते डिजिटल खतरों और संगठित अपराध से निपटने के लिए साइबर अपराध विरोधी इकाइयों और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है।
   - पुलिस बल में महिलाएं: लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, बजट में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए समर्पित बैरक और सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में बिहार की अग्रणी स्थिति को बनाए रखना है।
2. **''डिजिटल बिहार'' और ई-गवर्नेंस:** अध्याय 8 में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के

लिए ''डिजिटल बिहार'' पहल के व्यापक विस्तार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

- **डेटा एकीकरण:** सरकार डिजिटल कृषि निदेशालय को सामान्य प्रशासन के डेटा के साथ एकीकृत करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान सम्मान निधि जैसे लाभ आधार-सक्षम निर्बाध हस्तांतरण के माध्यम से वितरित किए जाएं।
- **सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) का विस्तार:** सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) पोर्टल को 100 से अधिक नई डिजिटल सेवाओं को शामिल करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

3. **न्यायिक अवसंरचना और कारागार सुधार:** न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, बजट में आधुनिक न्यायालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की गई है।
   - **जेलों का आधुनिकीकरण:** सभी केंद्रीय और जिला जेलों में उच्च-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी निगरानी और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
   - **कैदियों के लिए कौशल प्रशिक्षण:** एक नई पहल के तहत कैदियों की रिहाई के बाद उनके सफल सामाजिक पुनर्एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जेलों के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
4. **प्रशासनिक दक्षता: ''कार्यस्थल पर निवास'' मॉडल:** इस अध्याय की एक अनूठी विशेषता प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने की योजना है, जिसके तहत अधिकारियों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जाएगा।
   - **एकीकृत पंचायत भवन:** 2,666 नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के बाद पंचायत स्तर के कर्मचारियों (राजस्व अधिकारी, पंचायत सचिव) के लिए आवासीय क्वार्टर भी उपलब्ध होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें।
5. **पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी:** अध्याय 8 में एक उन्नत परिणाम बजटिंग ढांचा प्रस्तुत किया गया है।
   - **रीयल-टाइम ट्रैकिंग:** अब प्रत्येक विभाग को एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इससे वित्त विभाग यह निगरानी कर सकेगा कि ₹1,22,155 करोड़ की योजना का व्यय जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव में तब्दील हो रहा है या नहीं, जैसे कि प्रशिक्षित युवाओं की संख्या या निर्मित सड़कों की लंबाई।

अध्याय 8 की मुख्य बातों का सारांश

स्तंभ	फोकस क्षेत्र	मुख्य आवंटन/लक्ष्य
पुलिस	गृह विभाग	सुरक्षा के लिए ₹20,000 करोड़ से अधिक
डिजिटाइजेशन	ई-शासन	एआई-आधारित यंत्रीकरण और डेटा एकीकरण
न्याय	त्वरित-ट्रैक न्यायालय	आधुनिक न्यायिक अवसंरचना
शासन	स्थानीय उपस्थिति	2,666 पंचायत भवनों में आवासीय क्वार्टर

बिहार सरकार की नई नीतियां/विधेयक

नीति/विधेयक	प्रमुख विशेषताऐं
बिहार सेमीकंडक्टर नीति, 2026	इस नीति का उद्देश्य बिहार में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य में उच्च-तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा करना है।
बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025	**BIADA** द्वारा प्रबंधित औद्योगिक भूमि का **75%** भाग **CBG** (संपीड़ित जैव-गैस) परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। **CBG** इकाइयों के लिए अनुमोदन अवधि **31** मार्च **2027** तक बढ़ा दी गई है, जबकि द्वितीयक औद्योगिक सीमा **31** मार्च **2028** तक बढ़ा दी गई है।
नई और नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2025	इस नीति का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और **2029-30** तक **23,968** मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ-साथ **6,100** मेगावाट-घंटे ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करना है।
बिहार सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2025	इस विधेयक के तहत सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, चुनावों में देरी रोकने और गबन पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष प्राधिकरण के गठन की अनुमति दी गई है। वित्तीय अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पंप भंडारण नीति, 2025	आधुनिक ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विकसित करने और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
बिहार सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2024	इसका उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) को बढ़ावा देना है।
बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024	इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित प्रथाओं को रोकना है। दोषियों को 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
बिहार निषेध नीति, 2024	इसका उद्देश्य बिहार में शराबबंदी के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को मजबूत करना है।
बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति, 2024	इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का विकास करना है।

नीति/विधेयक	प्रमुख विशेषताएं
बिहार वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	इस विधेयक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है और कर संबंधी नियमों को सरल बनाया गया है।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	इस विधेयक में आयोग के सदस्यों की मौजूदा संख्या को बरकरार रखा गया है ताकि नियुक्तियों में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाई जा सके।
बिहार खेल नीति, 2024	राज्य के विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले युवाओं को 10 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चमड़ा) नीति, 2024 (संशोधन)	नई उत्पादन इकाइयों को 10 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
बिहार जैव द्रव्यमान संवर्धन नीति, 2023	बिहार सरकार बायोमास उत्पादन संयंत्र स्थापित करने वाले नए निवेशकों को परियोजना लागत पर 15% की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी।
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023	चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देता है।
बिहार रसद नीति, 2022	राज्य में रसद अवसंरचना को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था।

बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप्स/पोर्टल

ऐप/पोर्टल	जारी करने वाला प्राधिकरण	उद्देश्य
ई-विधान ऐप (नेवा)	संसदीय कार्य विभाग और राज्य विधानमंडल	सभी राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों का डिजिटलीकरण करना।
ई-मार्ग ऐप	सड़क निर्माण विभाग	सड़क की स्थिति की निगरानी करने और रखरखाव एवं मरम्मत के रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए
एचआरएमएस ऐप	बिहार सरकार	बिहार सरकार के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों (सेवा पुस्तिकाओं) का डिजिटलीकरण करना।
ई-रोस्ट्रम एसईसी बीआईएचआर ऐप	बिहार राज्य चुनाव आयोग	चुनावों का प्रबंधन करना और उनका सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
प्रवासी कामगार ऐप	श्रम संसाधन विभाग	राज्य के बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करना।
परिदर्शन पोर्टल	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	ताकि भूस्वामियों को अपने भूमि संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करने में सुविधा हो सके।
ई-डीएआर पोर्टल	परिवहन विभाग (राज्य एवं केंद्र)	सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रक्रिया को डिजिटल बनाना।
संजानी पोर्टल	शिक्षा विभाग	विश्वविद्यालय में प्रवेश, परीक्षा परिणामों और अन्य शैक्षणिक अभिलेखों से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
नीतीश ऐप	आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	बिजली गिरने की चेतावनी लगभग 30 मिनट पहले प्रदान करने के लिए।
द विलेज ऐप	आपदा प्रबंधन विभाग	कक्षा 10 और 12 के छात्रों को उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करना।
सुविधा वाहिनी पोर्टल	बिहार पुलिस	पुलिस विभाग के आंतरिक कामकाज और प्रशासन को सुगम बनाना।
ई-शिक्षा कोष ऐप/पोर्टल	शिक्षा विभाग	शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना और शैक्षिक योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
ई-मापी पोर्टल	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	भूमि माप से संबंधित सेवाओं को डिजिटाइज और सुव्यवस्थित करना।
ई-अमृत ऐप	स्वास्थ्य विभाग	गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था को सुगम बनाना।
ई-सत्य ऐप	बिहार पुलिस	त्वरित और सटीक डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाना।
मौसम बिहार ऐप	योजना एवं विकास विभाग	चौबीसों घंटे सातों दिन मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना।
बीएसईबी मोबाइल ऐप	बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड	छात्रों को अध्ययन सामग्री और परीक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करना।
BEFQR ऐप	जल संसाधन विभाग	बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए।

ऐप/पोर्टल	जारी करने वाला प्राधिकरण	उद्देश्य
बीआईपी पोर्टल	स्वास्थ्य विभाग	33 अलग-अलग बीमारियों की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए।
हेरिटेज ट्री ऐप	बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड	विरासत वृक्षों का डेटाबेस तैयार करना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना।
फिल्मो पोर्टल	शिक्षा विभाग	कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नि: शुल्क शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।
फंडा ऐप	स्वास्थ्य विभाग	गर्भवती महिलाओं को देखभाल, निगरानी और चिकित्सा सलाह प्रदान करना।
WAMIS ऐप	बिहार जल प्रबंधन विभाग	राज्य में सभी निर्माण और अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करना।
श्रोता संवाद ऐप	बिल्डर्स और बायर्स फोरम	छोटे श्रमिकों को रोजगार के अवसर खोजने और नौकरी से संबंधित मुद्दों को हल करने में सहायता करना।
भर्ती आवेदन	सहकारिता विभाग	छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराना।
गृह दर्शन ऐप	गृह विभाग, बिहार	राज्य में कानून व्यवस्था प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए।
ई-निश्चय पोर्टल	पंचायती राज विभाग	हर घर नल जल योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए।
चक्र मोबाइल ऐप	बिहार पुलिस	बिहार में अपराधियों का व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।
अश्विनी ऐप	स्वास्थ्य विभाग	आशा कार्यकर्ता **(ASHA)** को उनकी दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए।
इंद्रवज्र ऐप	आपदा प्रबंधन विभाग	बिजली गिरने के बारे में लोगों को पहले से चेतावनी देना।
विद्यावाहिनी ऐप	शिक्षा विभाग	कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों को छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
सेवा समाधान पोर्टल	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन	सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों और सेवानिवृत्ति संबंधी मुद्दों का समाधान करना।

आईएसएफआर रिपोर्ट 2023: बिहार

- **बहुत घना जंगल (VDF): 387** वर्ग किमी
  - इन्हें **70%** या उससे अधिक के चंदवा घनत्व वाले जंगलों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का **0.41%** भाग वीडीएफ के अंतर्गत आता है।
- **मध्यम सघन वन (एमडीएफ): 3,284.21** वर्ग किमी
  - इन्हें **40%** और **70%** के बीच कैनोपी घनत्व वाले जंगलों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का **3.49%** हिस्सा एमडीएफ (मल्टी-डिग्री फील्ड) द्वारा कवर किया जाता है।
- **खुला वन (OF): 3,861.24** वर्ग किमी
  - इन्हें **10%** और **40%** के बीच कैनोपी घनत्व वाले जंगलों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **OF** बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के **4.10%** हिस्से को कवर करता है।
- **कुल भौगोलिक क्षेत्रफल: 94,163** वर्ग किमी
- **कुल वन क्षेत्र: 7,532.45** वर्ग किमी
  - पिछले आकलन की तुलना में **129.19** वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
- **वृक्ष आवरण: 2,370.21** वर्ग किमी **(2.51%)**
  - पिछले आकलन की तुलना में **123.98** वर्ग किलोमीटर की कमी आई है।
- **कुल वन और वृक्ष आवरण: 9,902.66** वर्ग किमी **(10.52%)**
- **झाड़ीदार क्षेत्र: 260.80** वर्ग किमी **(0.28%)**

जिलेवार वन आवरण

- **कैमुर:** भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार में सबसे बड़ा वन क्षेत्र इसी क्षेत्र में है।

1. इसके **3,362** वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में से **1,026.68** वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
2. यह जिले के कुल क्षेत्रफल का **30.51%** है।

- **वन आवरण के आधार पर शीर्ष तीन जिले:**

1. **कैमुर**- **1,026.68** वर्ग किमी
2. **पश्चिम चंपारण**- **908.23** वर्ग किमी
3. **जमुई**- **670.84** वर्ग किमी

- **शेखपुरा:** इस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है।

1. इसके **689** वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में से केवल **0.82** वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
2. यह जिले के क्षेत्रफल का **0.12%** है।

- **वन आवरण के आधार पर सबसे निचले तीन जिले:**

1. **शेखपुरा**- **0.82** वर्ग किमी
2. **अरवाल**- **4.02** वर्ग किमी

3. **बक्सर**– 6.01 वर्ग किमी

वन आवरण में परिवर्तन

- **उच्चतम सकारात्मक परिवर्तन:**
  - **भागलपुर:** +33.82 वर्ग किमी
  - **मधुबनी:** +25.71 वर्ग किमी
- **उच्चतम नकारात्मक परिवर्तन:**
  - **कैमुर:** -35.35 वर्ग किमी
  - **नवादा:** -9.76 वर्ग किमी
- **बिहार में वन क्षेत्र में कुल वृद्धि:** 129.19 वर्ग किमी

बिहार में बांस के संसाधन

- बिहार में बांस का भंडार बढ़ रहा है।
- **आरएफए/ग्रीन वॉश के अंतर्गत बांस से आच्छादित क्षेत्र:**
  - **2023:** 1,109 वर्ग किमी
  - **2021:** 1,103 वर्ग किमी

बिहार के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले

- **कैमुर**– सबसे अधिक वन क्षेत्र (~1,026 वर्ग किमी; जिले के क्षेत्रफल का लगभग 30.5%)
- पश्चिम चंपारण– दूसरा सबसे ऊँचा स्थान (वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का घर)
- जमुई– तीसरा सबसे बड़ा (~670.84 वर्ग किमी; जिले के क्षेत्रफल का लगभग 21.65%)
- **नवादा, रोहतास और मुंगेर:** बिहार के महत्वपूर्ण वन-समृद्ध जिले भी हैं।

परियोजना / अभियान	शुरू	लक्ष्य / उपलब्धि	प्रमुख विशेषताऐं
जल-जीवन-हरियाली अभियान	2019	सात वर्षों में **21.25** करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।	बिहार का सबसे बड़ा पर्यावरण अभियान। जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर केंद्रित। **2024-25** में **4.06** करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और **2025-26** में **3.38** करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।
हरित जीविका, हरित बिहार	2019-20	जीविका दीदी द्वारा **4** करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।	जीविका स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इसमें नर्सरी प्रबंधन और आजीविका सृजन शामिल है।
कैम्पा (क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण)	चल रहे	प्रतिवर्ष लाखों पौधे लगाए जाते हैं	गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करता है।
कृषि वानिकी योजना	–	**40.68 लाख पौधे 2025-26** में लक्षित	यह किसानों की निजी जमीनों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं।
वार्षिक वृक्षारोपण अभियान 2025-26	मानसून 2025	**5 करोड़ पौधे 66** प्रजातियों में	विश्व पर्यावरण दिवस (**5** जून) को इसका शुभारंभ किया गया। भागलपुर में **1.30** करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार बिहार का कार्बन भंडार

- **कुल कार्बन भंडार:** 58,451 हजार टन (लगभग **58.45** मिलियन टन)।
- **2021 की तुलना में वृद्धि:** लगभग **1,570** हजार टन (**1.57** मिलियन टन)।
- इस अनुमान में बिहार भर में वन आवरण, वृक्ष आवरण और वनों के बाहर के वृक्षों (टीओएफ) में संग्रहित कार्बन शामिल है।

सीसीईए ने बिहार में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में **177** किलोमीटर तक फैली **₹3,169** करोड़ की परियोजना, भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी।
- बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर पर एक नए मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर के लिए भी मंजूरी दी गई, जो **82** किलोमीटर लंबी और **₹4,447** करोड़ की परियोजना है।

प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया

खबरों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट **2025** की पहल के तहत बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया।
- सरकार ने इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए **475** करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।

बिहार राज्य महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, बिहार राज्य महिला आयोग आज अपना **24वां** स्थापना दिवस मना रहा है।
- बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना **19** सितंबर, **2001** को हुई थी।
- इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा भी उपस्थित थीं।

मधुबनी का जितवारपुर गांव बिहार का पहला हस्तशिल्प गांव बनने जा रहा है।

खबरों में क्यों?

- मधुबनी का जितवारपुर गांव बिहार का पहला हस्तशिल्प गांव बनने जा रहा है।
- मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव, जो मिथिला चित्रकला की जीवंत परंपरा को संजोए हुए है, अब एक नए इतिहास के मुहाने पर खड़ा है। इसकी दीवारों पर उकेरे गए रंग अब केवल कला की विरासत बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि पूरे गांव को एक 'शिल्प गांव' में बदल देंगे।
- लगभग 400 परिवारों वाले इस गांव ने देश को तीन पद्म श्री पुरस्कार विजेता कलाकार दिए हैं। जगदंबा देवी (1975), सीता देवी (1980) और बौआ देवी (2017) को मिथिला चित्रकला के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है।
- क्राफ्ट विलेज परियोजना के लिए कुल 9 करोड़ 2 हजार 470 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 80 प्रतिशत, यानी 7.20 करोड़ रुपये, वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 1.80 करोड़ रुपये बिहार संग्रहालय द्वारा वहन किए जाएंगे।
- बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए रांती (मधुबनी), रैयाम (दरभंगा), भुसरा (मुजफ्फरपुर) और ठरकट्टी (गया) को नए शिल्प ग्राम (शिल्पग्राम) के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को बहुप्रतीक्षित पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

बिहार में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई

खबरों में क्यों?

- हाल ही में बिहार सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है।
- अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 428 रुपये प्रति दिन, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 444 रुपये प्रति दिन, कुशल श्रमिकों के लिए 541 रुपये प्रति दिन और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपये प्रति दिन निर्धारित की गई है।

बिहार को दो नए रामसर स्थल मिले।

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, बिहार में दो आर्द्रभूमि - बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील - को रामसर का दर्जा प्राप्त हुआ है।
- बिहार का पहला रामसर स्थल बेगुसराय जिले में स्थित कंवर झील (जिसे कबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है) है।
- बिहार के दूसरे और तीसरे रामसर स्थल जमुई जिले में स्थित नागी और नकाटी पक्षी अभयारण्य हैं।

गोकुल जलाशय के बारे में

- स्थान: बिहार के बक्सर में स्थित।
- यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक धनुषाकार झील है।

उदयपुर झील के बारे में

- यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है।
- यह एक धनुषाकार झील भी है, जिसके उत्तर और पश्चिम में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का घना जंगल स्थित है।

रामसर सम्मेलन के बारे में

- रामसर कन्वेंशन, जिसे आधिकारिक तौर पर आर्द्रभूमि कन्वेंशन कहा जाता है, पर 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे।
- रामसर सूची विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है, जिसमें 173 अनुबंधित पक्षों में फैले 2,500 से अधिक रामसर स्थल शामिल हैं, जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं।

पहला रामसर स्थल

- पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में नामित किया गया था।
- ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी।

बिहार के शैलेश कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, बिहार के जमुई जिले के हाई जम्पर शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चौंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।

ऑपरेशन आहट

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, मानव तस्करी विरोधी एक बड़े अभियान में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने समस्तीपुर, दानापुर और पटना जैसे संवेदनशील स्टेशनों पर बाल श्रम से कई बच्चों को बचाया।

बिहार में चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की

खबरों में क्यों?

- 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित बिहार की अंतिम मतदाता सूची में 74.2 मिलियन मतदाता हैं, जो 24 जून, 2025 को दर्ज किए गए 78.9 मिलियन मतदाताओं से लगभग 6% की कमी है। 24 जून, 2025 को

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में तीन महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- नाम हटाना और जोड़ना: मसौदा सूची से 65 लाख नाम हटा दिए गए, जिनमें मृत्यु, प्रवास और नामों की पुनरावृत्ति प्रमुख श्रेणियां थीं।
- दावों और आपत्तियों के बाद अंतिम चरण में अतिरिक्त 36.6 मिलियन नाम हटा दिए गए।
- गैर-नागरिकों या विदेशियों की संख्या नगण्य थी।
- अंतिम सूची में 21.53 मिलियन नए मतदाता जोड़े गए।
- 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची (72 मिलियन) की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 1.79 मिलियन की वृद्धि हुई है।
- लिंग प्रतिनिधित्व: एसआईआर के पूरा होने के बाद जनवरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 47.75% से थोड़ा घटकर 47.15% हो गया।

NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी सेंटर, मुजफ्फरपुर, बिहार

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से एनआईईएलआईटी डिजिटल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया, जो उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक मंच है।
- जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर (बिहार), बालासोर (ओडिशा), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), लुंगलेई (मिजोरम) और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएचडीडी) के केंद्र शासित प्रदेश दमन में पांच नए एनआईईएलआईटी केंद्रों का आभासी उद्घाटन किया।

बिहार विधानसभा के 18वें चुनाव

खबरों में क्यों?

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि 6 अक्टूबर 2025 घोषित किए जाने के तुरंत बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
- चुनाव दो चरणों में होंगे: पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का कार्यक्रम

- कुल सीटें: 121

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का कार्यक्रम

- कुल सीटें: 122

मखाना महोत्सव 2025, पटना, बिहार में

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, बिहार बागवानी निदेशालय ने 4 और 5 अक्टूबर के बीच पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया।
- केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 'मखाना महोत्सव 2025' में भाग लिया।
- इस अवसर पर उन्होंने 'मखाना: संस्कृति से समृद्धि तक' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- बिहार वैश्विक मखाना उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा रखता है, जहां इसकी खेती लगभग 3,000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,000-40,000 हेक्टेयर हो गई है, और निर्यात अब यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों तक पहुंच रहा है।

बिहार ने राष्ट्रीय स्वात चौंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदक जीते

खबरों में क्यों?

- हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय स्वात चौंपियनशिप में बिहार के मुक्केबाजों ने 10 स्वर्ण, छह रजत और आठ कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीते। बिहार ने कुल मिलाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

''छोटी चिरैया'' बनी बिहार की चुनावी आइकन!

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, राज्य में चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, छोटी चिरैया को बिहार की चुनावी पहचान बनाने का निर्णय लिया गया।
- इस उद्देश्य के लिए, राज्य स्तरीय शुभंकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नालंदा जिले के राहुल कुमार द्वारा बनाए गए ''छोटी चिरैया'' को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि मधुबनी जिले के कृपा नाथ झा द्वारा बनाए गए 'मातृज' को द्वितीय पुरस्कार मिला।

प्रधानमंत्री 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' अभियान शुरू करेंगे:

खबरों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' अभियान के तहत बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।

इस राज्य में हर साल सड़क हादसों में 8,873 लोगों की मौत होती है।

खबरों में क्यों?

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की नई रिपोर्ट ''भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023'' के अनुसार, बिहार में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 8,873 लोगों की मृत्यु हुई।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन 24 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए रात्रि रक्त सर्वेक्षण शुरू

खबरों में क्यों?

- स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
- बिहार के विभिन्न ब्लॉकों की पंचायतों में 13 से 25 अक्टूबर तक रात्रि रक्त सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
- चुनिंदा स्थानों पर रात के समय रक्त के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं।
- सभी क्षेत्रों में फाइलेरिया के संभावित रोगियों की पहचान करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग रात 8: 30 बजे से रक्त के नमूने लेना शुरू करता है और यह प्रक्रिया आधी रात तक जारी रहती है।

बिहार की अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या

खबरों में क्यों?

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस खिलाड़ी विद्या कुमारी ने अपनी खेल प्रतिभा से बिहार का नाम रोशन किया है।
- सुश्री विद्या बिहार की एक अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण, 2 कांस्य और 16 रजत पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं।
- सुश्री विद्या बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं। वह विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया बुजुर्ग उत्तरी पंचायत की रहने वाली है.

तीरंदाजी प्रशिक्षक जय प्रकाश को बिहार राज्य खेल पुरस्कार प्राप्त होगा

खबरों में क्यों?

- गया जिले के तीरंदाजी प्रशिक्षक जय प्रकाश को बिहार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- जिले के प्रसिद्ध तीरंदाजी प्रशिक्षक जय प्रकाश को इस वर्ष बिहार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।

बिहार में 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप हैं।

खबरों में क्यों?

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच (बीईडब्ल्यू) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आपराधिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- विषय: एडीआर और बीईडब्ल्यू द्वारा किया गया यह विश्लेषण 6 नवंबर, 2025 को होने वाले बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 1,314 उम्मीदवारों में से 1,303 उम्मीदवारों के स्व-घोषित शपथ पत्रों पर आधारित है।
- इन निष्कर्षों से उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों और आर्थिक पृष्ठभूमि दोनों पर प्रकाश पड़ता है।

आपराधिक पृष्ठभूमि:

- 423 उम्मीदवारों (32%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
- 354 उम्मीदवारों (27%) पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
- 33 उम्मीदवारों ने हत्या के आरोपों को स्वीकार किया है, जबकि 86 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए गए हैं।
- 42 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिनमें बलात्कार के 2 मामले शामिल हैं।
- वित्तीय पृष्ठभूमि: 519 उम्मीदवार (40%) करोड़पति हैं (जिनकी घोषित संपत्ति ₹1 करोड़ या उससे अधिक है)।

बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, नालंदा में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, नव नालंदा महाविहार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बिहार का पहला पांडुलिपि समूह केंद्र घोषित किया गया है।
- यह उपलब्धि ''ज्ञान भारतम'' पहल के तहत हासिल की गई है।

पटना नगर निगम की 'पिंक इनोवेशन' को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, पटना नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
- कॉर्पोरेशन की नवोन्मेषी पहल, ''पिंक इनोवेशन'', को मार्च 2026 में नीदरलैंड के डेल्फ्ट में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ''रेजिलिएंट सिस्टम्स 2026'' के लिए चुना गया है।
- इस सम्मेलन में पटना नगर निगम भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन समिति ने बिहार (भारत) के पटना नगर निगम द्वारा प्रस्तुत ''पिंक इनोवेशन: जल निकासी और स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखना और सतत विकास लक्ष्य 2026 को प्राप्त करना'' शीर्षक वाली प्रस्तुति को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

बिहार के चार उत्पाद राष्ट्रीय डिजिटल बाजार (ई-एनएएम) में शामिल किए गए।

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, बिहार के चार जीआई-टैग वाले उत्पादों को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार (ई-एनएएम) में शामिल किया गया है, जिनमें भागलपुर का

जरदालू आम, कटारनी चावल, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मगही पान शामिल हैं।

- भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन उत्पादों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
- किशनगंज से सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट भी जल्द ही इस बाजार में शामिल किए जाएंगे, जिससे राज्य में जैविक खेती और डिजिटल वाणिज्य को एक नई गति मिलेगी।

गोगबील झील: भारत का नया (94वां) रामसर स्थल

भारत ने बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर सूची में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की भारत की 94वीं आर्द्रभूमि बन गई है। यह कदम आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत पारिस्थितिक प्रबंधन के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गोगबील झील के बारे में

- यह गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित एक धनुषाकार झील है।
- यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है।
- मानसून के मौसम में, यह स्वाभाविक रूप से दोनों नदियों से जुड़ जाता है और बाढ़ के मैदान की आर्द्रभूमि के रूप में कार्य करता है।
- यह अब बिहार का छठा रामसर स्थल बन गया है (अन्य स्थलों में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील आदि शामिल हैं)।

स्तन के दूध में यूरेनियम का पता लगाना

बिहार के छह जिलों की माताओं के स्तन दूध में यूरेनियम की पहचान चिंताजनक है। मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **प्रचलन:** भोजपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की सभी 40 भाग लेने वाली माताओं के स्तन के दूध के नमूनों में यूरेनियम (यू-238) पाया गया।

भारत में मुफ्त दवा वितरण में बिहार पहले स्थान पर है।

मरीजों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार:

हाइलाइट

- बिहार ने अक्टूबर 2023 में 81.35 अंक हासिल किए और पहला स्थान बरकरार रखा।
- राजस्थान (77.77) दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पंजाब (71.80) तीसरे स्थान पर रहा।
- बिहार पूरे एक साल से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

- **मतदान की तिथियां:** दो चरण – 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025
- **परिणाम:** 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के लिए घोषणा की गई।
- **मतदाता:** कुल 7.43 करोड़ पंजीकृत मतदाता
  - 3.92 करोड़ पुरुष
  - 3.50 करोड़ महिलाएं
  - 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता

सीट वितरण

- कुल सीटें: 243
  - **203 सामान्य**
  - **38 अनुसूचित जाति (एससी)**
  - **2 अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)**

संदर्भ: पिछला चुनाव (2020)

- **विजयी गठबंधन:** राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)
  - जीती गई सीटें: 125 (स्पष्ट बहुमत)
  - प्रमुख दल: भाजपा और जेडीयू
- **सबसे बड़ी एकल पार्टी:** राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 75 सीटों के साथ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NOTA

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में, NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प को कुल वैध वोटों का 1.81% प्राप्त हुआ – जो 2020 में 1.68% से थोड़ी वृद्धि है, लेकिन फिर भी 2015 में दर्ज 2.48% से कम है।

- **कुल NOTA वोट:** 6,65,870
- मामूली वृद्धि मतदाताओं की कुछ हद तक असंतुष्टि को दर्शाती है, हालांकि एनडीए ने लगभग 200 सीटों पर जीत हासिल करके स्पष्ट जनादेश प्राप्त कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के बाद NOTA को लागू किया गया था, जिसने मतदाताओं को गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया। हालांकि, NOTA को सबसे अधिक वोट मिलने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता है।

बिहार चुनाव 2025: मतदान के आंकड़े

चरण	कुल मतदान (%)	पुरुषों का मतदान (%)	महिला मतदान (%)
चरण एक	65.08%	61.2%	70.4%
2 चरण	68.76%	64.4%	72.8%
कुल मिलाकर	**66.91%**	**62.8%**	**71.6%**

मुख्य विशेषताएं

1. **महिलाओं की मतदान भागीदारी (71.6%) पुरुषों की मतदान भागीदारी (62.8%) से काफी अधिक थी।**
2. **2020 की तुलना में कुल मतदान में 9% से अधिक की वृद्धि हुई।**

बिहार चुनाव 2025: प्रमुख राजनीतिक गठबंधन

गठबंधन का नाम	प्रमुख दल	गठबंधन नेता
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)	जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (रामविलास), आरएलजेडी, हम	नीतीश कुमार (जेडीयू)

गठबंधन का नाम	प्रमुख दल	गठबंधन नेता
महागठबंधन / भारत गठबंधन	आरजेडी, इंक, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, वीआईपी, अन्य वामपंथी दल	तेजस्वी यादव (आरजेडी)
नई/स्वतंत्र पार्टियां	जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर के नेतृत्व में), अन्य	प्रशांत किशोर

अंतिम सीट गणना: एनडीए का दबदबा

- **भाजपा:** 89 सीटें
- **जेडीयू:** 85 सीटें
- **एलजेपी (राम विलास):** 19 सीटें
- **आरजेडी:** 25 सीटें
- **कांग्रेस:** 6 सीटें
- **एआईआईएमआईएम:** 5 सीटें
- **हैम(एस):** 5 सीटें
- **राष्ट्र लोक मोर्चा (आरएलएसएचटीकेएम):** 4 सीटें
- **सीपीआई (एमएल) मुक्ति:** 2 सीटें
- **सीपीआई(एम):** 1 सीट
- **भारतीय समावेशी पार्टी:** 1 सीट
- **बीएसपी:** 1 सीट

महिला नेताओं की भागीदारी

बिहार विधानसभा के 2025 चुनावों में महिलाओं ने ऐतिहासिक 29 सीटें हासिल कीं:

- **एनडीए से 26**
- **महागठबंधन से 3**

महिलाओं की सबसे बड़ी जीत:

- **रामा निषाद (भाजपा) – औराई:** 57,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की।
- **लेशी सिंह (जेडीयू)– धमदाहा:** 55,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की।

युवा उपलब्धि हासिल करने वाले:

- **मैथिली ठाकुर (भाजपा), उम्र 25:** सबसे कम उम्र की महिला विधायक।
- **छोटी कुमारी (उम्र 28)** और कोमल सिंह (जेडीयू) ने भी प्रभावशाली जीत हासिल की।

सबसे करीबी प्रतियोगिता विजेता

निर्वाचन क्षेत्र	विजेता (पार्टी)	उपविजेता (पार्टी)	अंतर
संदेश (भोजपुर)	राधा चरण साह (जेडीयू)	दीपू सिंह (आरजेडी)	**27 वोट**
अगियाओन (भोजपुर)	महेश पासवान (भाजपा)	सीपीआई-एमएल उम्मीदवार	**95 वोट**

सबसे बड़ी जीत का अंतर

रैंक	निर्वाचन क्षेत्र	विजेता	दल	अंतर
1	रुपौली	कलाधर प्रसाद मंडल	जदयू	**73,572**
2	सुगौली	राजेश कुमार (बबलू गुप्ता)	एलजेपी (आरवी)	**58,191**
3	दीघा	संजीव चौरसिया	भाजपा	**59,079**

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)

चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एक स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है।

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 324:** चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास है।
- **अनुच्छेद 325:** किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 326:** चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
- **अनुच्छेद 327:** संसद चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है।
- **अनुच्छेद 328:** राज्य विधानसभाएं अपने चुनावों से संबंधित कानून बना सकती हैं।
- **अनुच्छेद 329:** जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

बिहार में तीन नए रेल गलियारे

दैनिक यात्रा की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, तीन प्रमुख रेल गलियारों को विकसित किया जाएगा और उन्हें पटना रिंग रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

कॉरीडोर

1. **पूर्व-पश्चिम गलियारा:** बक्सर से किउल
2. **उत्तरी गलियारा:** फतुहा–पटना–छपरा–सोनेपुर–हाजीपुर–मुजफ्फरपुर
3. **केंद्रीय गलियारा:** पटना–फतुहा–बख्तियारपुर–बिहारशरीफ–तिलैया–गया–जहानाबाद

प्रमुख बुनियादी ढांचा

- **कुल नए ट्रैक:** 260 किमी
- **प्रमुख पुल:**
  - दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा नदी पर बना 10 किलोमीटर लंबा रेल पुल
  - छह लेन वाली कच्ची दरगाह–बिदुपुर पुल के समानांतर
- **अनुमानित लागत:** ₹9,000 करोड़
- **सर्वेक्षण की स्वीकृति:** रेलवे बोर्ड द्वारा 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए

डॉ. प्रेम कुमार

भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ. प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और नौ बार विधायक चुने जा चुके हैं।

बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष

गया अर्बन से भाजपा विधायक डॉ. प्रेम कुमार को विधानसभा का 18वां अध्यक्ष चुना गया है।

बिहार विधानसभा का इतिहास

स्वतंत्रता-पूर्व इतिहास

- **प्रथम वक्ता:** 1937 के चुनावों के बाद राम दयालु सिंह (मुजफ्फरपुर के गंगवा गांव के निवासी और किसान आंदोलन के नेता) पहले स्पीकर चुने गए थे।
- **भवन का इतिहास:** वर्तमान विधानमंडल भवन का निर्माण 1920 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के सचिवालय के रूप में किया गया था। पहली बैठक 1921 में सर वाल्टर माउड की अध्यक्षता में हुई थी और राज्यपाल लॉर्ड एस.पी. सिन्हा ने संबोधित किया था।

संरचनात्मक परिवर्तन

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा अलग-अलग प्रांत बन गए।
- बिहार विधान परिषद को उच्च सदन बनाकर द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। परिषद की पहली बैठक 22 जुलाई 1936 को हुई थी।
- 1937 के चुनावों में सदस्यों की संख्या बढ़कर 152 हो गई और डॉ. श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली जिम्मेदार सरकार का गठन हुआ।
- 22 जुलाई 1937 को, दोनों सदनों के पहले संयुक्त सत्र के दौरान, राम दयालु सिंह को अध्यक्ष चुना गया।

राजनीतिक घटनाक्रम

- 1939 में, डॉ. श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरोध में इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग कर दी गई।
- 1945 के चुनावों के बाद, डॉ. श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार की पुनः स्थापना हुई।

पोस्ट-आजादी

- 1946 में, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद पहले स्पीकर बने।
- जनसंख्या वृद्धि के कारण, सदस्यों की संख्या में कई बार परिवर्तन हुआ (उदाहरण के लिए, 1952 में 330, 1977 में 325 जिसमें एक मनोनीत सदस्य भी शामिल था)।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

प्रारंभिक जीवन

- **जन्म:** 3 दिसंबर 1884, जीरादेई, सीवान, बिहार
- **मृत्यु:** 28 फरवरी 1963, पटना

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

- 1920 में, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए अपने सफल कानूनी करियर को छोड़ दिया।
- नमक सत्याग्रह (1931) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में भाग लेने के लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई थी।
- कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष (1934)।
- सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 में वे फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने।

संविधान निर्माण में भूमिका

- संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष (1946)।
- कई महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व किया:
  - राष्ट्रीय ध्वज समिति
  - नियम समिति
  - वित्त समिति
  - कर्मचारी एवं प्रक्रिया समिति

लिखी गई पुस्तकें

- चंपारण में सत्याग्रह(1922)
- विभाजित भारत(1946)
- आत्मकथा(1946)
- बापू के कदमों में(1954)

पुरस्कार

- उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया (1962)।

भारत के राष्ट्रपति के रूप में

- 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने।
- उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक सेवा की, जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है।
- एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें दो बार सर्वसम्मति से पुनः चुना गया (1952 और 1957)।

बिहार सरकार की युवाओं के लिए एक बड़ी पहल

लक्ष्य: 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां

सरकार का लक्ष्य 2030 तक युवाओं को 1 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

तीन नए विभागों का गठन

1. युवा, रोजगार और कौशल विकास
2. उच्च शिक्षा
3. नागरिक उड्डयन

नीतीश कुमार ने लंदन स्थित विश्व अभिलेख पुस्तिका में अपना नाम दर्ज कराया।

बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का नाम लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है।

मान्यता का कारण: विश्व रिकॉर्ड पुस्तिका ने नीतीश कुमार को राजनीति में उनके असाधारण योगदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और भारत के राजनीतिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि - दसवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद, नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को दसवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने पहली बार 3 मार्च 2000 को यह पद संभाला था और कुल मिलाकर 19 वर्ष और 3 महीने से अधिक समय तक इस पद पर रहे हैं, जिससे वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं।

नागरिक सुरक्षा जिला

- मंत्रिमंडल की बैठक में गया और मुंगेर जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया, जिससे राज्य में ऐसे जिलों की कुल संख्या 30 हो गई।

गया:

- एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र।
- बौद्ध स्थलों, पितृ पक्ष के मेलों और बौद्ध त्योहारों के कारण यहां साल भर तीर्थयात्री आते रहते हैं।
- भीड़ प्रबंधन और संभावित आपदाओं (प्राकृतिक या मानव निर्मित) के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता है।

मंगर:

- औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण, यहाँ जमालपुर रेल फैक्ट्री, ऐतिहासिक ब्रिटिश गन फैक्ट्री और आईटीसी स्थित हैं।
- संभावित खतरों के कारण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नागरिक सुरक्षा के बारे में:

- नागरिक सुरक्षा एक संगठनात्मक ढांचा है जिसका गठन आपदाओं, युद्ध या किसी भी आपात स्थिति के दौरान नागरिकों की रक्षा, बचाव और सहायता करने के लिए किया जाता है।
- इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जागरूकता बढ़ाना और आवश्यकता पड़ने पर राहत प्रदान करना है।
- भारत में, नागरिक सुरक्षा की स्थापना नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत की गई है और इसका संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

मंत्रिमंडल की बैठक से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ

1. **युवा कौशल विकास:** वित्तीय साक्षरता और निवेश ज्ञान पर केंद्रित छात्र कौशल कार्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन।
1. **अवसंरचना विकास:** राज्य की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के साथ सहयोग।
2. **वन्य जीवन की बातचीत:**

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फाउंडेशन : इसकी स्थापना 15 करोड़ रुपये के कोष के साथ की जाएगी।
- पटना स्थित संजय गांधी जैविक पार्क के प्रबंधन और विकास के लिए एक समिति का गठन।

3. **रश्मी रानी:**
   - सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय योगदान और सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रभाव के लिए सम्मानित।
   - ज्ञान उदय फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इंडियन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ इन्फ्लुएंसर श्रेणी में चयनित।
4. **ऊर्जा संग्रहालय (विद्युत संग्रहालय):**
   - पटना के कर्बिगहिया स्थित बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की लगभग 3 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय विकसित किया जाएगा।
   - **संचालक:** बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी।
   - **महत्व:** भारत का पहला और दुनिया का चौथा समर्पित ऊर्जा संग्रहालय।

63वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चौंपियनशिप 2025

- **पीयूष दयाल:** पटना के खिलाड़ी ने अंडर-18 पुरुषों की इनलाइन फ्रीस्टाइल क्लासिक श्रेणी में कांस्य पदक जीता।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

- अपनी बैठक में, केंद्रीय मखाना विकास योजना और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया।
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर और अन्य अनुसंधान संस्थानों को चालू और आगामी वर्ष के लिए गुणवत्तापूर्ण मखाना बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया था।

राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (एनआरसी), दरभंगा:

- केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार गठित।
- इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 15 सितंबर 2025 को बिहार में किया गया।
- सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक मखाना विकास के लिए 476.03 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी।

बिहार बोर्ड को तीन अंतरराष्ट्रीय आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुए

पटना: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी) को शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में एक साथ तीन अंतरराष्ट्रीय आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि के साथ, बिहार बोर्ड तीनों प्रमाणपत्र एक साथ प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बोर्ड बन गया है।

बीएसईबी को प्राप्त आईएसओ प्रमाणपत्र:

- **आईएसओ 9001: 2015**- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
- **आईएसओ/आईईसी 27001: 2022**- सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
- **आईएसओ 15489-1: 2016**- अभिलेख प्रबंधन प्रणाली

काग्यू मोनलम चेन्मो

महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे कग्यु मोनलाम चेनमो की सात दिवसीय प्रार्थना सभा विश्व शांति के लिए प्रार्थनाओं के साथ शुरू होगी।

- इस कार्यक्रम का नेतृत्व काग्यू संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख, 17वें ग्यालवा कर्मापा, ओग्येन ट्रिनले दोरजे करेंगे।

सात निश्चय-3 (सात निश्चय-3)

24 नवंबर 2005 को सरकार बनने के बाद, बिहार ने 'न्याय के साथ विकास' की नीति का पालन करते हुए अव्यवस्था और पिछड़ेपन से विकास की ओर निर्णायक रूप से कदम बढ़ाया।

इसके सफल कार्यान्वयन के बाद:

- **सात निश्चय (2015-2020)**और
- **सात निश्चय-2 (2020-2025),**

सरकार ने बिहार को भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए सात निश्चय-3 को लागू करने का निर्णय लिया है।

सात निश्चय-3 के तहत सात प्रतिबद्धताएँ:

1. **दोहरा रोजगार - दोहरी आय**
   - प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखें।
   - मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत:
     - » स्वरोजगार के लिए ₹10,000
     - » व्यवसाय विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक
   - **94 लाख गरीब परिवार:** जाति आधारित और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से पहचाने गए लोगों को रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
   - अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
   - युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन।
2. **समृद्ध उद्योग - सशक्त बिहार**
   - बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाएं और इसे पूर्वी भारत के तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करें।
   - उद्योग एवं निवेश के मुख्य सचिव के अधीन उच्च स्तरीय समितियाँ।
   - सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र।
   - पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का लक्ष्य।
   - 9 बंद चीनी मिलों का पुनरुद्धार और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना।
3. **कृषि प्रगति - राज्य की समृद्धि**
   - चौथी कृषि रोडमैप (2024-2029) का कार्यान्वयन।
   - उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए मखाना रोडमैप को बढ़ावा देना।
   - प्रत्येक पंचायत में सुधा मिल्क आउटलेट के माध्यम से डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
   - सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना।
4. **उन्नत शिक्षा - उज्ज्वल भविष्य**
   - पुरानी संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करना।
   - आधुनिक शिक्षा नगर की स्थापना।
5. **सुलभ स्वास्थ्य सेवा - सुरक्षित जीवन**
   - ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा।
   - जिला अस्पतालों को सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
6. **मजबूत नींव - आधुनिक विस्तार**
   - बुनियादी ढांचे, शहरी विस्तार, एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें।
   - पर्यटन विकास संबंधी पहल।
   - फिल्म सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और खेल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।
7. **सभी के लिए गरिमा - सुगम जीवन**
   - सुशासन और मानवीय प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करें।
   - प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से सेवाओं का सरलीकरण।

खेल विकास योजना

बिहार सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी खेल नीति के तहत 12 नए एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं।

खेल-कूद केंद्र:

- **बक्सर:** कबड्डी (लड़कों की)
- **सीतामढ़ी:** कबड्डी (लड़कियाँ)
- **मंगर:** फुटबॉल (लड़के)
- **नालंदा:** शूटिंग (लड़के), हॉकी (लड़कियां)
- **पटना:** कुश्ती (लड़के)
- **सिवान:** हैंडबॉल (लड़कियाँ)
- **कैमुर:** वॉलीबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स (लड़कों के लिए)
- **बेगुसराय:** ताइक्वांडो (लड़कों के लिए)

ऑपरेशन ''भूमि दखल देहानी''

बिहार सरकार ने भूमि संबंधी मामलों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए, त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशन भूमि दखल देहानी' शुरू किया है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थियों को भूमि का उचित कब्जा सुनिश्चित करना।
- जिला अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई।

युवा राष्ट्रीय खेल

- **बिहार पहली बार युवा राष्ट्रीय खेल 2028 की मेजबानी करेगा।**
- भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

पूर्णिया में मौसम रडार परियोजना

- **दूसरा आधुनिक मौसम रडार:** बिहार में पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में इसे स्थापित किया जा रहा है।
- **कुल लागत:** ₹57 करोड़

एकीकृत रोग निगरानी

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के अंतर्गत:

- **जहानाबाद जिला:** जनवरी–अक्टूबर 2025 के दौरान 783 जिलों में से 99.37 अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- **राज्य स्तर पर प्रथम स्थान.**

शीर्ष जिले:

1. अहमदाबाद (गुजरात) – 99.9
2. नयागढ़ (ओडिशा) – 99.48
3. जहानाबाद – 99.37
4. कंधमाल (ओडिशा) – 99.11
5. आनंद (गुजरात) – 99.04

बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव

बिहार सरकार निवेशकों के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बेंगलुरु में ''बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव'' का आयोजन कर रही है।

- औद्योगिक इकाइयों और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (बीआईएसएफ) की स्थापना का प्रस्ताव।
- घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैदराबाद और नई दिल्ली में ''बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026'' आयोजित करने की योजना है।
- बिहार विजन 2047 की दीर्घकालिक योजना के तहत, राज्य से पलायन को कम करने के लिए औद्योगिक विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दर्शन परिषद का 47वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ।

- बिहार दर्शन परिषद का 47वां वार्षिक सम्मेलन नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय (एनओयू), पटना में आयोजित किया गया।
- 48वां वार्षिक सम्मेलन मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में आयोजित किया जाएगा, जिसमें गया की पवित्र भूमि पर दार्शनिकों को एक साथ लाया जाएगा।

अनुकूल रॉय

बिहार के मुख्य सचिव ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025–26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अनुकूल रॉय को सम्मानित किया।

- **व्यक्तिगत उपलब्धि:** अनुकुल रॉय को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
- **सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025–26:** भारत का प्रमुख घरेलू टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट

टूर्नामेंट के परिणाम

- **विजेता:** झारखंड
- **द्वितीय विजेता:** हरयाणा
- **बिहार का प्रदर्शन:** क्वार्टर फाइनल में पहुंचे
- **टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी:** अनुकूल रॉय

राज्य पर्यटन विभाग

- बिहार में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से, राज्य पर्यटन विभाग एक पर्यटन मानचित्र, पर्यटन मोबाइल ऐप और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटक गाइडों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 200 पर्यटक गाइड हैं।
- 2024 में बिहार में कुल 6.6 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें से 98.9% घरेलू पर्यटक और लगभग 7.37 लाख विदेशी पर्यटक थे।

पटना उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **रितेश कुमार:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण कुमार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
- **नियुक्ति प्राधिकारी:** भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- **संवैधानिक आधार:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की गई नियुक्ति।
- **कॉलेजियम प्रणाली:** सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियाँ।
- **कुल शक्ति:** इन नियुक्तियों के साथ, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई है।

पटना उच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य

- **स्थापित:** 3 फरवरी 1916
- **कानूनी आधार:** भारत सरकार अधिनियम, 1915
- **प्रथम मुख्य न्यायाधीश:** सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चौम्प्स
- **वर्तमान मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित (बिहार)

- बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- **राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति:** इस प्रस्ताव को बिहार मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
- **अंतिम स्वीकृति:** अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।
- **बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य:** वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, जो भारत–नेपाल सीमा के निकट पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है।

छह जिलों में भूकंपीय वेधशालाएँ

- देश की भूकंप का पता लगाने और निगरानी करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए 100 नई भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें से छह बिहार में प्रस्तावित हैं। यह पहल राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा की जा रही है।

बिहार में प्रस्तावित जिले

- पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, औरंगाबाद

बिहार की भूकंपीय स्थिति

- बिहार हिमालय और विवर्तनिक प्लेटों के संगम के निकट स्थित है, जिसके कारण यह अत्यधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्र है।
- राज्य का लगभग 80% हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 (उच्च जोखिम) के अंतर्गत आता है।
- नए वर्गीकरण के अनुसार, मधुबनी और दरभंगा जैसे जिले अब भूकंपीय क्षेत्र 6 (अत्यधिक उच्च जोखिम) में हैं।
- **प्रमुख जोन-5 जिले:** किशनगंज,सहरसा,सुपौल,मधेपुरा,अररिया,सीतामढ़ी, दरभंगा,मधुबनी,भागलपुर,बांका,जमुई,मुंगेर,कटिहार और पूर्णिया।

सौर ऊर्जा-सह-बैटरी भंडारण परियोजना

- बिहार ने लखीसराय जिले के काजरा में 301 मेगावाट की सौर-ऊर्जा-प्लस-बैटरी भंडारण परियोजना के पहले चरण की शुरुआत कर दी है।

न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू

- **न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू:** उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

प्रमुख बिंदु

- **शपथ:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा प्रशासित।
- **संवैधानिक आधार:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर।
- **पूर्ववर्ती:** उन्होंने न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजनथारी, 46वें मुख्य न्यायाधीश (अक्टूबर 2025 तक) का स्थान लिया।
- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति सुधीर सिंह (6 जनवरी 2026 तक)।
- **पिछली पोस्ट:** उन्होंने ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

महारानी कमसुंदरी देवी

- **महारानी कमसुंदरी देवी:** दरभंगा राज की अंतिम जीवित रानी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वह अंतिम महाराजा, महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की विधवा थीं, जिन्हें ब्रिटिश भारत का सबसे धनी जमींदार माना जाता था।

ग्रामीण सड़कों के लिए क्यूआर कोड निगरानी

- बिहार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए क्यूआर कोड और एआई-आधारित प्रणाली शुरू की है।

रानी चाओ खुन फ्रा सिनानाथ बिलासक्ल्यानि

- **रानी चाओ खुन फ्रा सिनानाथ बिलासक्ल्यानि:** थाईलैंड के लोगों ने बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा, आराधना और ध्यान किया।

श्रेयस बी. चंद्र

- बिहार के औरंगाबाद के एक युवा वैज्ञानिक ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन-2026 में स्वर्ण पदक जीता।
- क्यूआर तकनीक पर आधारित एक विशेष डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई।
- पिछली उपलब्धियां:
  - अप्रैल 2022: महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक उपकरण विकसित किया।
  - अक्टूबर 2022: नासा द्वारा मान्यता प्राप्त दो क्षुद्रग्रहों की खोज की गई।

काठी स्क्रिप्ट

- बिहार ने काठी लिपि के 31 विशेषज्ञों के लिए पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।
- **काठी लिपि:** उत्तर भारत (बिहार, उत्तर प्रदेश, अवध, मिथिला) में 16वीं शताब्दी से कानूनी, प्रशासनिक और निजी दस्तावेजों के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपि।

विदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ

- राष्ट्रीय विदेश योजना के तहत, बिहार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र को ₹3.5-4 लाख आवंटित करने का प्रस्ताव।

बिहार: समृद्धि यात्रा

- पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले के नीतीश कुमार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
- **चरण 1:** 16-24 जनवरी 2026; इसमें 9 जिले शामिल हैं, जिसका समापन वैशाली जिले में होगा।

- **उद्घाटन समारोह:** मुख्यमंत्री ने कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में 153 करोड़ रुपये की लागत वाली 125 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 29 करोड़ रुपये की लागत वाली 36 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- ये परियोजनाएं मुख्य रूप से अवसंरचना विकास और औद्योगिक विस्तार पर केंद्रित थीं।

मल्टीमॉडल टर्मिनल

- **बलुघाटा, सोनपुरए:** क ऐसा मल्टीमॉडल टर्मिनल स्थापित करना जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 21.56 करोड़ टन कार्गो और 77,000 कंटेनरों की हो।

22 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया

- गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गृह मंत्रालय ने बिहार के 22 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की।
- इनमें से तीन कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में डीजी कुंदन कृष्णन, सेवानिवृत्त डीएसपी अर्जुन लाल और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शामिल हैं।

त्यागराजन एस.एम.

- नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के दौरान, जिला मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एस.एम. को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उल्लेखनीय नवाचारों के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- इसी अवसर पर, सीईओ कार्यालय की मीडिया टीम को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 – सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम पुरस्कार के लिए चुना गया।

अर्थशिला, पटना

- **'अर्थशिला'**यह बिहार के पटना के गोला रोड इलाके में स्थित एक ऊर्ध्वाधर सभागार है।
- यह इमारत जमीन से लगभग 60 फीट ऊपर दिखाई देती है, जबकि इसका मुख्य आकर्षण जमीन से लगभग 40 फीट नीचे स्थित है।
- यह बिहार का पहला सभागार है जिसमें भूमिगत मंचन की सुविधा है।

आर्किटेक्ट सौरभ गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया

- अर्थशिला की वास्तुकला ग्रीक थिएटर की अवधारणा से प्रेरित है, जो मंच और दर्शकों के बीच एक गहरा संबंध सुनिश्चित करती है।

अनाज एटीएम

- बिहार में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
- शुरुआत में, इसे शहरी पटना में एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें अनाज एटीएम के लिए तीन स्थानों का प्रस्ताव है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) अनाज एटीएम की खरीद, स्थापना, एक साल की वारंटी और एक साल के रखरखाव का प्रबंधन करेगा।
- ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा के बाद बिहार अनाज एटीएम के माध्यम से राशन वितरण शुरू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा।

मिडिल स्कूल उफ्रेल

- गणतंत्र दिवस के अवसर पर, बिहार के सह-प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उफ्रेल मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका अर्चना को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।
- यह सम्मान जिला और राज्य स्तर पर हरित एवं स्वच्छ विद्यालय रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त करने के लिए दिया गया था।
- इससे पहले, स्कूल ने 2021-22 और 2022-23 सत्रों के लिए लगातार बिहार राज्य स्वच्छता पुरस्कार में प्रथम स्थान भी हासिल किया था।

बिहार सेमीकंडक्टर नीति

बिहार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को राज्य के औद्योगिक भविष्य का नया इंजन बनाने के उद्देश्य से बिहार सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अगले पांच वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति मुख्यमंत्री के विजन 'सात निश्चय-3: समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त, बिहार सरकार 20% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

बिहार विधानसभा का आम बजट

आज बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस बार बिहार का कुल बजट 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बिहार भी कई अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है।

किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर बिहार सरकार ने 'जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति वर्ष ₹3,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी। यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

मखाना-लीची में नंबर वन, अब चावल-गेहूं पर ध्यान केंद्रित।

1. बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 326.62 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया।
2. मखाना और लीची उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है।

3. विश्व के लगभग 85% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है।
4. इसी कारण केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय मखाना बोर्ड' के गठन को मंजूरी दे दी है।
5. यह राज्य मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और चावल और गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है।
6. मशरूम उत्पादन में बिहार देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।

1.1 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र

वर्ष 2026-27 के बजट में बिहार सरकार ने घोषणा की कि आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति (बीपीएल) श्रेणी के 58 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र 100% सब्सिडी के साथ स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 10 लाख घरों पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे।

बिहार राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल): यह कंपनी देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी बनने जा रही है जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध होगी।

खेलों के लिए प्रयास

वर्ष 2026 के बजट में बिहार सरकार ने खेल क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट और दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 8,053 ग्राम पंचायतों और 154 नगर पंचायतों में खेल क्लबों के गठन को मंजूरी दे दी गई है। युवाओं को उनके अपने गांवों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5,341 खेल मैदानों का चयन किया गया है, जिनमें से 4,849 खेल मैदानों का निर्माण पूरा हो चुका है। पटना के पुनपुन क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर एक भव्य खेल केंद्र विकसित किया जाएगा, जिसके लिए ₹574.33 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 13 जिलों में ₹477.80 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक खेल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रस्तावित खेल आयोजन

- **2026:** एफआईएच हॉकी प्रो लीग की मेजबानी
- **2028:** राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी
- **2030:** हॉकी विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का लक्ष्य
- **2034:** बिहार ने 2034 में भव्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है।

डायनासोर पार्क

बिहार राज्य का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जाएगा। इस पार्क का विकास पूरी तरह से आधुनिक तकनीक की मदद से किया जाएगा।

वैभव सूर्यवंशी

जाइडस वेलनेस के प्रमुख पोषण पेय ब्रांड कॉम्प्लान ने उभरते भारतीय क्रिकेट सितारे और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपना नया राष्ट्रीय अभियान "थोड़ा प्लान, थोड़ा कॉम्प्लान" भी शुरू किया है।

सोनपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

- सोनपुर में पूर्वी भारत का पहला और देश का पांचवां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाना है।
- राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 1,302 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

"सुकन्या जिला" पहल-समस्तीपुर

समस्तीपुर जिले को "सुकन्या जिला" के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल शुरू की गई है।

- इस योजना का लक्ष्य पांच वर्ष से कम आयु की प्रत्येक बालिका तक इस योजना का विस्तार करना है।

डॉप्लर मौसम रडार

बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) चंपारण और भागलपुर जिलों में उन्नत डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करेगा।

बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित

मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सली गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- 2012 में बिहार के 23 जिले नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हुए थे।
- 1970 के दशक के दौरान, मध्य बिहार में नक्सली प्रभाव विशेष रूप से मजबूत था।
- केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों के कारण, 2025 में नक्सलवाद की एक भी घटना दर्ज नहीं की गई।
- 2025 में 220 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जो राज्य में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र

राजौली (नवादा) में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना चल रही है, जिसकी अनुमानित लागत ₹20,000 करोड़ है।

19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चौम्पियनशिप

सीमा यादव ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक आयोजित 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चौंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल चार पदक (3 स्वर्ण और 1 कांस्य) जीते।

सीमा यादव जमुई जिले के खैरा पुलिस थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की निवासी हैं।

प्रमुख उपलब्धियां:

- **300 मीटर राइफल प्रोन (व्यक्तिगत)**- स्वर्ण पदक
- **300 मीटर राइफल प्रोन (टीम)**- स्वर्ण पदक

- **300 मीटर तीन-स्थिति (व्यक्तिगत)**- कांस्य पदक
- **300 मीटर तीन-स्थिति (टीम)**- स्वर्ण पदक

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गांव

पवित्र नगर बोधगया में पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य ग्राम विकसित किया जाएगा।

बोधगया के ''नोड-1'' क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा और लगभग 4.2 एकड़ भूमि पर यह फूड विलेज स्थापित किया जाएगा।

सीवान का बेटा, बिहार का गौरव

भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर, मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपुन ने जिरादेई में आयोजित एक समारोह के दौरान 105 वर्षीय लोक गायक और स्वतंत्रता सेनानी जंग बहादुर सिंह को ''सिवान का पुत्र, बिहार का गौरव'' की उपाधि से सम्मानित किया।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जंग बहादुर सिंह ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की और ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए उत्पीड़न को भी सहन किया।

सैयद अता हसनैन

पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे।

जनरल हसनैन को सामरिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।

नागालैंड के नए राज्यपाल

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

वे पटना साहिब से कई बार विधायक चुने जा चुके हैं और बिहार में उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है।

औद्योगिक विकास

पारू क्षेत्र

बेला और मोतीपुर के बाद, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पारू क्षेत्र को जिले के नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस परियोजना के लिए पांच प्रमुख गांवों की भूमि का चयन किया गया है:

- चांदपुर चिउताहन
- चतुरपत्ती
- भोजपत्ती
- हरपुर कपरफोडा
- विशुनपुर सरैया

इकबाल हसन रिशु

बिहार में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में उनके योगदान के लिए, दरभंगा के डॉ. इकबाल हसन 'ऋषु' को नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें एक प्रशंसा पत्र और 10,000 रुपये से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें 'शांति दूत' के रूप में मान्यता दी गई।

पंखुड़ी सोनी

पंखुड़ी सोनी: पटना शहर की उभरती हुई फैशन पेशेवर को प्रतिष्ठित ''यंग वुमन अचीवर अवार्ड'' से सम्मानित किया गया है।

सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) और विंड्रो प्लांट

औरंगाबाद जिले के दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) और एक विंड्रो प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।

सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ)

एमआरएफ एक विशेष सुविधा है जहां शहर से एकत्रित कचरे को विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग किया जाता है।

यहां मशीनों की मदद से प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच जैसे सूखे कचरे को अलग किया जाएगा।

विंडरो प्लांट

विंडरो संयंत्र मुख्य रूप से गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करेगा। इस प्रक्रिया में, कचरे को एक विशिष्ट तरीके से फैलाया जाता है और प्राकृतिक रूप से विघटित और सुखाया जाता है, जिससे जैविक खाद (उर्वरक) का उत्पादन होता है।

मुफ्त दवाइयों की उपलब्धता में बिहार पहले स्थान पर है

बिहार: फरवरी 2026 में मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने में भारत में पहला स्थान हासिल किया।

जीविका दीदी की आवाज केंद्र

जीविका और पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप के बीच हुए एक समझौते के तहत पटना में एक ''जीविका दीदी की आवाज केंद्र'' स्थापित किया जाएगा।

यह केंद्र चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर स्थापित किया जाएगा।

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026

नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है, जो भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करता है।

एफएचआई 2026 में विस्तारित कवरेज

- पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों का आकलन किया गया था।
- नए संस्करण में उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में से 10 को भी शामिल किया गया है।
- निष्पक्ष तुलना के लिए, इन राज्यों का अलग-अलग मूल्यांकन और रैंकिंग की गई है क्योंकि इनकी आर्थिक और भौगोलिक स्थितियां प्रमुख राज्यों से काफी भिन्न हैं।

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के पाँच स्तंभ

यह सूचकांक पांच प्रमुख स्तंभों के आधार पर राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है:

1. **व्यय की गुणवत्ता**– यह आकलन करता है कि राज्य सार्वजनिक धन को कितनी कुशलता से खर्च करते हैं।
2. **राजस्व जुटाना**– यह करों और अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने की राज्यों की क्षमता का मापन करता है।
3. **वित्तीय विवेक**– यह मूल्यांकन करता है कि राज्य घाटे और व्यय का प्रबंधन कितनी जिम्मेदारी से करते हैं।
4. **ऋण सूचकांक**– यह राज्य सरकारों के ऋण के स्तर और संरचना पर नजर रखता है।
5. **ऋण स्थिरता**– यह राज्यों की समय के साथ ऋण का प्रबंधन और भुगतान करने की क्षमता का आकलन करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 (प्रमुख राज्य) के मुख्य बिंदु

वर्ग	राज्य अमेरिका	प्रमुख विशेषताऐं
एचीवर्स	**ओडिशा, गोवा, झारखंड**	**ओडिशायह** राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जो मजबूत राजकोषीय अनुशासन और कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शन करता है।
अग्रणी दावेदार	**गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक**	इन राज्यों का वित्तीय प्रदर्शन स्थिर है, हालांकि उनके अंक अचीवर राज्यों की तुलना में थोड़े कम हैं।
कलाकार	**मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान**	ये राज्य अपेक्षाकृत संतुलित राजकोषीय संरचनाएं बनाए रखते हैं, लेकिन मध्यम घाटे और सीमित राजकोषीय लचीलेपन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं।
उम्मीदवार	**पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब**	उच्च घाटे, बढ़ते ऋण स्तर और कम विकासात्मक व्यय के कारण इन राज्यों को लगातार वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है।

बिहार का बलिराजगढ़ किला

मधुबनी जिले में स्थित बलिराजगढ़ किले के खंडहरों को हाल ही में स्थल पर नए सिरे से खुदाई करने की अनुमति मिली है।

इस स्थल को आधिकारिक तौर पर ''गढ़ के प्राचीन किले के अवशेष'' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि स्थानीय लोग इसे ''राजा बलि का गढ़'' कहते हैं। इस स्थल की पहचान सर्वप्रथम 1884 में ब्रिटिश अधिकारी और विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने की थी, जो उस समय मधुबनी के एसडीएम थे।

डॉ. महेंद्र झा

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. महेंद्र झा को उनकी कालजयी कृति ''धात्री पात सं गाम'' के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।

कार्य के बारे में:

- **प्रकृति:** काल्पनिक नहीं, बल्कि लेखक के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित।
- **विषय:** ग्रामीण जीवन, सामाजिक ताने-बाने और मिथिला संस्कृति के सार को दर्शाता है।

उन्होंने 1971 से 2004 तक सहरसा कॉलेज में मैथिली के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के पीजी सेंटर में विभागाध्यक्ष (एचओडी) और मानविकी के डीन भी रहे।

2009 में सेवानिवृत्ति के बाद भी वे लिखना जारी रखते हैं।

अन्य रचनाएँ: दिक्पाल, पथांतर

सिद्धांत सारंग

बिहार के प्रमुख लोक त्योहार छठ पूजा पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुई है।

यह केस स्टडी युवा विद्वान सिद्धांत सारंग द्वारा लिखी गई है।

उन्हें 2019 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल डायना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान

बिहार में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी-आईएसआरओ) और बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र (बीएमएसकेसी) के सहयोग से मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक को लागू किया जा रहा है।

बिहार का 114वां स्थापना दिवस

22 मार्च, 2026 को बिहार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और राष्ट्रीय शुभकामनाओं के साथ अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया।

- 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। उसी दिन उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा) का भी गठन हुआ, जो बाद में 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य बन गया।
- **थीम:** ''उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार'' (विकसित बिहार, उज्ज्वल बिहार)।

100 नए हवाई अड्डों की योजना – बिहार में 4

केंद्र सरकार ने बिहार के चार शहरों – गोपालगंज, बेगुसराय, भागलपुर और छपरा सहित देश भर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास की योजना को मंजूरी दे दी है।

- वर्तमान में पटना और दरभंगा प्रमुख विमानन केंद्र हैं, जबकि गया और पूर्णिया में सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं।
- पूर्णिया में एक सिविल टर्मिनल का निर्माण और मुजफ्फरपुर के पताही हवाई पट्टी का पुनरुद्धार अंतिम चरण में है।
- सोनपुर (सारण जिले) में एक नए हवाई अड्डे के लिए भी मंजूरी दे दी गई है।

नीतीश कुमार का इस्तीफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद, उन्होंने उच्च सदन में जाने का फैसला किया।

राजनीतिक कैरियर

- **1985:** नालंदा विधानसभा सीट से विधायक के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
- **1989:** पहली बार नौवीं लोकसभा के सदस्य बने।
- **2006 से:** बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में लगातार राज्य का नेतृत्व किया।
- **2026:** राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कई निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन गए:

- शराबबंदी (शराब पर प्रतिबंध)
- छात्राओं के लिए साइकिल योजना
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा

कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की शिक्षा दी जाएगी।

शैक्षिक ढांचा और डिजिटल प्लेटफॉर्म:

यह एआई प्रोग्राम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित होगा। शिक्षण कार्य डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में वीडियो सर्च और रीड-अलाउड टूल्स जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं, जिससे छात्रों को विषयों को समझना आसान हो जाता है और उनकी डिजिटल लर्निंग में सुधार होता है।

शिक्षा विभाग के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, ''एआई के लिए कौशल विकास'' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एआई से संबंधित आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाएगा।

वेस्टर्न सोन नहर पर सौर ऊर्जा संयंत्र

राज्य सरकार ने वेस्टर्न सोन नहर के तटबंध पर 10 मेगावाट का एक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

सिंचाई के लिए 'आशा मॉडल'

राज्य सरकार द्वारा विकसित 'आशा मॉडल' एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक और आधुनिक सिंचाई विधियों को जोड़ती है। इसके तहत, आहार-पाइन जैसे पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाता है और उन्हें सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़ा जाता है।

इस योजना का पहला कार्यान्वयन पटना जिले के पालीगंज ब्लॉक में किया जा रहा है। यहां 7 एकड़ के आहार का नवीनीकरण किया गया है और पास ही के 1 एकड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

रग्बी प्रतियोगिता

- भुवनेश्वर स्थित केआईएसएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय पुरुष और महिला रग्बी प्रतियोगिता में, टीएमबीयू की दोनों टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट/सर्विस अवार्ड-2026

- निदेशालय को मखाना मूल्य श्रृंखला में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 'गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट/सर्विस अवार्ड-2026' से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा दिया जाता है, और इसका चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय जूरी द्वारा किया गया था।
- देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा अकेले बिहार से आता है।
- मखाना अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ''बिहार ब्रांड'' के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

- राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने पटना के नंदलाल छपरा में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए लगभग 5.68 एकड़ भूमि का चयन किया जा चुका है।

बिहारवन

- बिहार सरकार ने 'बिहारवन' डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 87 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया है।
- बिहारवन एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एक ही ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से कई सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

जोर शीतल महोत्सव

- मैथिली भाषी समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को जोर शीतल उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।
- यह शीतलता, स्वास्थ्य और पारिवारिक आशीर्वाद का प्रतीक है।
- इस दिन लोग संग्रहित (बासी) पानी से स्नान करते हैं और देवी शीतला की पूजा करते हैं।
- परंपरागत रूप से, इसे सतुआनी (सतुआन) के अगले दिन मनाया जाता है।

सम्राट चौधरी बिहार के 21वें मुख्यमंत्री बने।

- भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- यह समारोह पटना के राजभवन में आयोजित किया गया था।
- उन्हें राज्यपाल सैयद अता हसनैन द्वारा शपथ दिलाई गई।

- बिहार में लगभग दो दशकों के राजनीतिक वर्चस्व के बाद नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिया।
- सम्राट चौधरी इससे पहले उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का भी कार्यभार संभाला है।

बिहार के मुख्यमंत्री (1946-2026)

- श्री कृष्ण सिंह – 1946 से 1961 (सबसे लंबा कार्यकाल)
- दीप नारायण सिंह – 1961 (बहुत कम समय का कार्यकाल)
- बिनोदानंद झा – 1961 से 1963
- कृष्ण बल्लभ सहाय – 1963 से 1967 तक
- महामाया प्रसाद सिन्हा – 1967 से 1968 तक
- सतीश प्रसाद सिंह – 1968 (बहुत ही संक्षिप्त कार्यकाल)
- बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल – 1968
- भोला पासवान शास्त्री – एकाधिक कार्यकाल (1968-1971)
- हरिहर सिंह – 1969
- दारोगा प्रसाद राय – 1970
- कर्पूरी ठाकुर – दो बार (1970-71, 1977-79)
- केदार पांडे – 1972 से 1973
- अब्दुल गफूर – 1973 से 1975
- जगन्नाथ मिश्रा – तीन बार (1975-77, 1980-83, 1989-90)
- राम सुन्दर दास – 1979 से 1980 तक
- चंद्रशेखर सिंह – 1983 से 1985
- बिंदेश्वरी दुबे – 1985 से 1988 तक
- भागवत झा आजाद – 1988 से 1989 तक
- सत्येन्द्र नारायण सिन्हा – 1989
- लालू प्रसाद यादव – 1990 से 1997 तक
- राबड़ी देवी – तीन कार्यकाल (1997-2005)
- नीतीश कुमार – कई कार्यकाल (2000, 2005-2014, 2015-2026) – 10 बार शपथ ली (रिकॉर्ड)
- जीतन राम मांझी- 2014 से 2015

महत्वपूर्ण तथ्यों

- सबसे लंबा कार्यकाल – श्री कृष्ण सिंह (1946-1961)
- सबसे अधिक बार शपथ ग्रहण करने वाले – नीतीश कुमार (10 बार)
- पहली महिला मुख्यमंत्री – राबड़ी देवी
- सबसे कम कार्यकाल – दीप नारायण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह
- दो बार के मुख्यमंत्री – कर्पूरी ठाकुर
- तीन बार के सीएम-जगन्नाथ मिश्रा, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार
- **2026 में मुख्यमंत्री – सम्राट चौधरी (भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, 24वें मुख्यमंत्री)**

मिथिला चित्रकला-महिलाओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई

ऐसे समय में जब पारंपरिक कलाएं धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं, बिहार की महिला कलाकारों ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और रचनात्मकता के माध्यम से मिथिला चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है।

महत्वपूर्ण तथ्यों:

- अब तक मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में 9 कलाकारों को पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है – जिनमें से 8 महिलाएं हैं।
- बिहार की लोक कलाओं में 16 कलाकारों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है – जिनमें से 12 महिलाएं हैं।

मिथिला की प्रमुख पद्म श्री पुरस्कार विजेता महिला चित्रकारी कलाकार

1. **जगदंबा देवी (मधुबनी)**
   - मिथिला चित्रकला के पहले प्रमुख कलाकार माने जाते हैं
   - कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (1975)
2. **सीता देवी (सुपौल)**
   - उन्होंने अपनी मां और दादी से चित्रकला सीखी।
   - 1960 के दशक में, दीवार चित्रों को कागज पर उतारा गया, जिससे कला को एक नया आयाम मिला।
   - उनकी पेंटिंग्स की मांग दिल्ली, अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी में थी।
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (1981)
3. **गंगा देवी (मधुबनी)**
   - गरीबी और पारिवारिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपनी कलात्मक यात्रा जारी रखी।
   - उनकी कचनी शैली की चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली।
   - उन्होंने जापान, अमेरिका और फ्रांस में मिथिला की चित्रकला का प्रदर्शन किया।
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (1984)
4. **महासुंदरी देवी**
   - कागज से परे विस्तारित मिथिला चित्रकला
   - साड़ियों, लकड़ी और प्लाईवुड पर कलाकृतियाँ बनाईं।
   - इसने अरिपान की पारंपरिक कला को वैश्विक मान्यता दिलाई।
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (2011)
5. **बौआ देवी (मधुबनी)**
   - भरनी शैली के लिए प्रसिद्ध
   - इसमें पौराणिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषय भी शामिल थे।
   - पेरिस, जापान और जर्मनी में आयोजित प्रदर्शनियाँ
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (2019)
6. **गोदावरी दत्त (दरभंगा)**
   - कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कला को अपना जीवन बना लिया।
   - समुद्र मंथन, अर्धनारीश्वर और त्रिशूल जैसे कार्यों के लिए जाने जाते हैं

- इस कला रूप से हजारों महिलाओं को जोड़ा गया
- **पुरस्कार:** पद्म श्री (2019)

7. **दुलारी देवी (मधुबनी)**
   - बचपन गरीबी में बीता।
   - दूसरों के घरों में काम करते हुए मैंने पेंटिंग सीखी।
   - उनकी पेंटिंग्स अब भारत और विदेशों की गैलरीज में प्रदर्शित की जाती हैं।
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (2021)
8. **शांति देवी (मधुबनी)**
   - पारंपरिक गोदना शैली को कागज और कैनवास कला में रूपांतरित किया गया
   - उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक नायकों और सामाजिक विषयों को शामिल किया।
   - **पुरस्कार:** पद्म श्री (2024)

वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर

बिहार सरकार पटना के निकट एक वैश्विक मॉडल शिक्षा नगर स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **स्थान एवं क्षेत्र:** पटना के पास 250 एकड़ से अधिक भूमि पर इसका विकास किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इसे बिहार में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना।
- **बजट:** अनुमानित प्रारंभिक लागत लगभग ₹547 करोड़ है।

16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चौम्पियनशिप 2026

यह चौंपियनशिप बिहार के राजगीर में आयोजित की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- **कार्यक्रम का स्थान:** राजगीर खेल परिसर
- **व्यवस्था करनेवाला:** हॉकी इंडिया
- **सहभागिता:** भारत भर से लगभग 30 टीमें

विजेता:

- **स्वर्ण पदक:** उत्तर प्रदेश हॉकी ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराया
- **रजत पदक:** मध्य प्रदेश
- **कांस्य पदक:** पंजाब ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को हराया

कैमूर हिल्स में उच्च सुरक्षा वाली जेल

बिहार सरकार कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल स्थापित करने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य:** कुख्यात अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें जेल के अंदर से आपराधिक नेटवर्क संचालित करने से रोकने के लिए।
- **जगह:** कैमूर जिले का सरोदग गांव, भाभुआ से लगभग 76 किलोमीटर दूर, घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर

नीतीश कुमार ने पटना के पास दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहटा हवाई अड्डे परियोजना के निर्माण का निरीक्षण किया।

एलिवेटेड कॉरिडोर - मुख्य विशेषताएं:

- **लंबाई:** लगभग 25 किमी
- **का हिस्सा:** पटना-बक्सर चार लेन सड़क परियोजना
- **विशेषता:** पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की उम्मीद है
- **कनेक्टिविटी:** आगामी बिहता हवाई अड्डे से सीधा संपर्क स्थापित होगा।

बिहता हवाई अड्डा परियोजना

- पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में इसका विकास किया जा रहा है।
- **पहला हवाई अड्डा:** जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (स्थापना 1973 में हुई)

राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान (बिहार)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के अंतर्गत अप्रैल 2026 में बिहार में पोषण पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किया। ये गतिविधियाँ बेगुसराय जिले में आयोजित की गईं।

एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस)

- बिहार में सड़क हादसों को कम करने के लिए, 700 से 800 दुर्घटना संभावित स्थानों पर एक एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) स्थापित की जाएगी।
- आईटीएमएस आधुनिक एआई-आधारित तकनीक का उपयोग करेगा। यह यातायात नियमों के उल्लंघन का स्वचालित रूप से पता लगाने और ई-चालान जारी करने में सक्षम होगा।

बिहार राज्य राजमार्ग चार परियोजना

- बिहार राज्य राजमार्ग चार परियोजना के तहत लगभग 266.168 किलोमीटर लंबाई की सड़कों में और सुधार किया जाएगा।
- इस पर लगभग ₹3,743 करोड़ 65 लाख 50 हजार खर्च किए जाएंगे।

पांच सड़क परियोजनाओं का विवरण:

- **प्रोजेक्ट 1:** -मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना पथ
  - लंबाई: 38.872 किमी
  - लागत: ₹632 करोड़ 72 लाख
- **परियोजना 2:** एसएच-52 सीतामढी-पुपरी-बेनीपट्टी पथ
  - लंबाई: 51.261 किमी
  - लागत: ₹435 करोड़ 37 लाख

- **परियोजना 3:** एसएच-97 विशनपुर-अतरबेल (एनएच-57) जाले घोघरचट्टी (एसएच-52) पथ
  - लंबाई: 47.875 किमी
  - लागत: ₹990 करोड़ 3 लाख 50 हजार
- **परियोजना 4:** एसएच-92 गणपतगंज-परवाहा पथ
  - लंबाई: 47.432 किमी
  - लागत: ₹703 करोड़ 95 लाख
- **परियोजना 5:** ब्रह्मपुर-कोरनासराय-इटाढ़ी-सरंजा-इटाढ़ी बक्सर और उजियारपुर-कुकरहा-जमुआंव-इंदौर-समदा पथ
  - लंबाई: 80.728 किमी
  - लागत: ₹982 करोड़ 58 लाख
- सड़क परियोजनाओं के अलावा, कोसी सिंचाई योजना और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए ₹102.98 करोड़ जारी किए गए हैं।

मधुबनी में नहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इससे लगभग 89 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

बिहटा (पटना) में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बिहटा जिले के सिकंदरपुर में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में स्थापित विस्तार केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया।

बिहटा में स्थित इस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 171 करोड़ रुपये की लागत से की गई है।

कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना के अंतर्गत उद्यमिता जागरूकता और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

लीची का डंक मारने वाला कीट – कार्य बल का गठन

बिहार में लीची किसानों को हो रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लीची स्टिंग बग के कारण फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए एक विशेषज्ञ कार्य दल के गठन का निर्देश दिया।

डंक मारने वाला कीड़ा एक प्रकार का कीट है जिसका हमला लीची के फलों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है – फल सिकुड़ने लगते हैं, समय से पहले गिरने लगते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं।

बिहार लीची का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहां मुजफ्फरपुर की लीची को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार 2026

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में बत्तीस (32) नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

दलों के अनुसार मंत्रियों का वितरण

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) – 15 मंत्री (243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते)
- जनता दल (यूनाइटेड) – JDU – 13 मंत्रियों ने शपथ ली (कुल 15 मंत्रियों में से 13 ने आज शपथ ग्रहण की)
- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)-एलजेपी- 2 मंत्री
- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM)- 1 मंत्री
- राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो)- 1 मंत्री

भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।

अनुच्छेद 164 के अनुसार, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक ही मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं।

मालभोग केला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हाजीपुर (वैशाली जिले) के प्रसिद्ध मालभोग केले को तो लाम को विशेष उपहार के रूप में भेंट किया।

मालभोग केला, जिसे ''बिहार का गौरव'' भी कहा जाता है और असम में चंपा केला कहा जाता है, केले के सिल्क (एएबी) समूह से संबंधित एक उत्कृष्ट किस्म है।

यह अपने अनूठे स्वाद, सुगंध, बनावट और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है।

यह विटामिन सी, विटामिन बी6, पोटेशियम और आहार फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है।

भगवान महावीर स्वामी की 72 फुट ऊंची प्रतिमा

बिहार की राजधानी पटना के गुलजारबाग में स्थित पवित्र कमलदाह जी क्षेत्र में एक भव्य और ऐतिहासिक जैन तीर्थ स्थल का निर्माण किया जा रहा है। यह स्थल महान जैन आचार्य स्थूलीभद्र स्वामी के ध्यान स्थल और श्रेष्ठी सुदर्शन स्वामी की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ है।

- यह विशाल परिसर लगभग 1,00,000 वर्ग फुट (लगभग 5.04 एकड़) में फैला होगा और पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित किया जाएगा।
- इस परिसर में महावीर स्वामी की 72 फुट ऊंची प्रतिमा होगी, जिसे 36 फुट ऊंचे कमल के आसन पर स्थापित किया जाएगा।
- इस प्रकार, संरचना की कुल ऊंचाई 108 फीट हो जाएगी।

आचार्य स्थूलीभद्र स्वामी के बारे में

- आचार्य स्थूलीभद्र स्वामी (लगभग 297 ईसा पूर्व) जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे।
- वह राजा धनानंद के मंत्री शकताल के पुत्र थे।
- अपने प्रारंभिक गृहस्थ जीवन का त्याग करके, वे आचार्य संभूत्विजया के शिष्य बन गए।

प्रथम विश्व योगासन खेल चौम्पियनशिप 2026

बिहार के पांच प्रतिभाशाली योगासन खिलाड़ियों को प्रथम विश्व योगासन खेल चौंपियनशिप 2026 में भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है।

चयनित खिलाड़ी और उनकी विशेषज्ञताएँ

1. सुधांशु शेखर – बैकवर्ड बेंड
2. दिलीप कुमार – फॉरवर्ड बेंड
3. सारांश कुमार – लयबद्ध जोड़ी
4. सोनी कुमारी – पैरों का संतुलन
5. साक्षी कुमारी – बैकवर्ड बेंड

- यह चौंपियनशिप जून 2026 में ट्रांसस्टेडिया, अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की जाएगी।
- इसका आयोजन वर्ल्ड योगासन द्वारा किया जा रहा है और इसकी मेजबानी योगासन भारत कर रहा है।

डॉ. जया भारती

बिहार के धनरुआ ब्लॉक की डॉ. जया भारती को जर्मनी के ब्रैंडेनबर्ग राज्य में आयोजित एक भव्य समारोह में ''प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग'' श्रेणी में ''सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान पुरस्कार 2026'' से सम्मानित किया गया।

- वर्तमान में, डॉ. जया पॉट्सडैम विश्वविद्यालय में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं।
- उनका शोध हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री पर केंद्रित है।

बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से शुरू किए गए बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 4,750 करोड़ रुपये) के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- इस राशि का उपयोग शहरी शासन को मजबूत करने, नागरिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं में सुधार करने और नियोजित शहरी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

गंगा पथ (मरीन ड्राइव) परियोजना

बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के किनारे महत्वाकांक्षी गंगा पाथवे (मरीन ड्राइव) परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह राज्य की पहली सड़क परियोजना है जिसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएम) के तहत विकसित किया जा रहा है।

यह परियोजना लगभग 83 किलोमीटर लंबी होगी।

निर्माण कार्य दो चरणों में होगा:

- **पहला चरण:** सफियाबाद हेरुदियारा से सुल्तानगंज तक बरियापुर और घोरघाट होते हुए लगभग 42 किलोमीटर सड़क का निर्माण।
- **दूसरा चरण:** सुल्तानगंज से भागलपुर और सबौर तक लगभग 40.80 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)

बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वैशाली जिले के हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में, इस संस्थान के लिए भारत सरकार को 100 एकड़ भूमि नि: शुल्क उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

परियोजना का रणनीतिक महत्व और प्रभाव:

- **खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापना:** हाजीपुर के विकासशील औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह संस्थान बिहार को देश के अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण राज्यों में से एक के रूप में उभरने में मदद करेगा।
- **किसानों और युवाओं का सशक्तिकरण:** इस संस्थान के माध्यम से, स्थानीय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त होगी, जबकि युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी।

इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

इस नीति के अंतर्गत प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन और लाभ:

- **ई-कार (महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान):** अपने नाम से इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं को सरकार से 1 लाख रुपये तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिलेगी।
- **ई-टू व्हीलर्स:**
  - सामान्य वर्ग के लिए ₹10,000 तक की सब्सिडी।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) श्रेणियों के लिए ₹12,000 तक की सब्सिडी।
- **ई-थ्री व्हीलर्स (मालवाहक वाहन):**
  - सामान्य वर्ग के लिए ₹50,000 तक की सहायता राशि।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ₹60,000 तक की सहायता राशि।
- **कर प्रोत्साहन:** राज्य में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी।

अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन:

- **चार्जिंग नेटवर्क:** इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और बड़ी इमारतों में चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- **परिवहन रोजगार योजना:** युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए एक नई परिवहन रोजगार योजना शुरू की जाएगी।

नीति के अपेक्षित परिणाम और दीर्घकालिक लक्ष्य:

- **ईंधन की बचत:** इस नीति के माध्यम से, राज्य का लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल और डीजल की वार्षिक खपत को लगभग 10 करोड़ लीटर तक कम करना है।

- **इलेक्ट्रिक वाहन पैठ लक्ष्य:** सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक राज्य में बिकने वाले प्रत्येक 100 नए वाहनों में से कम से कम 30 वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए।

पिरपैंती ताप विद्युत परियोजना

बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए निर्णायक वित्तीय राहत प्रदान की है।

राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के पट्टे के दस्तावेजों पर लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह (100%) माफ कर दिया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कुल 1,020.60 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, जिसे 33 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा रहा है।

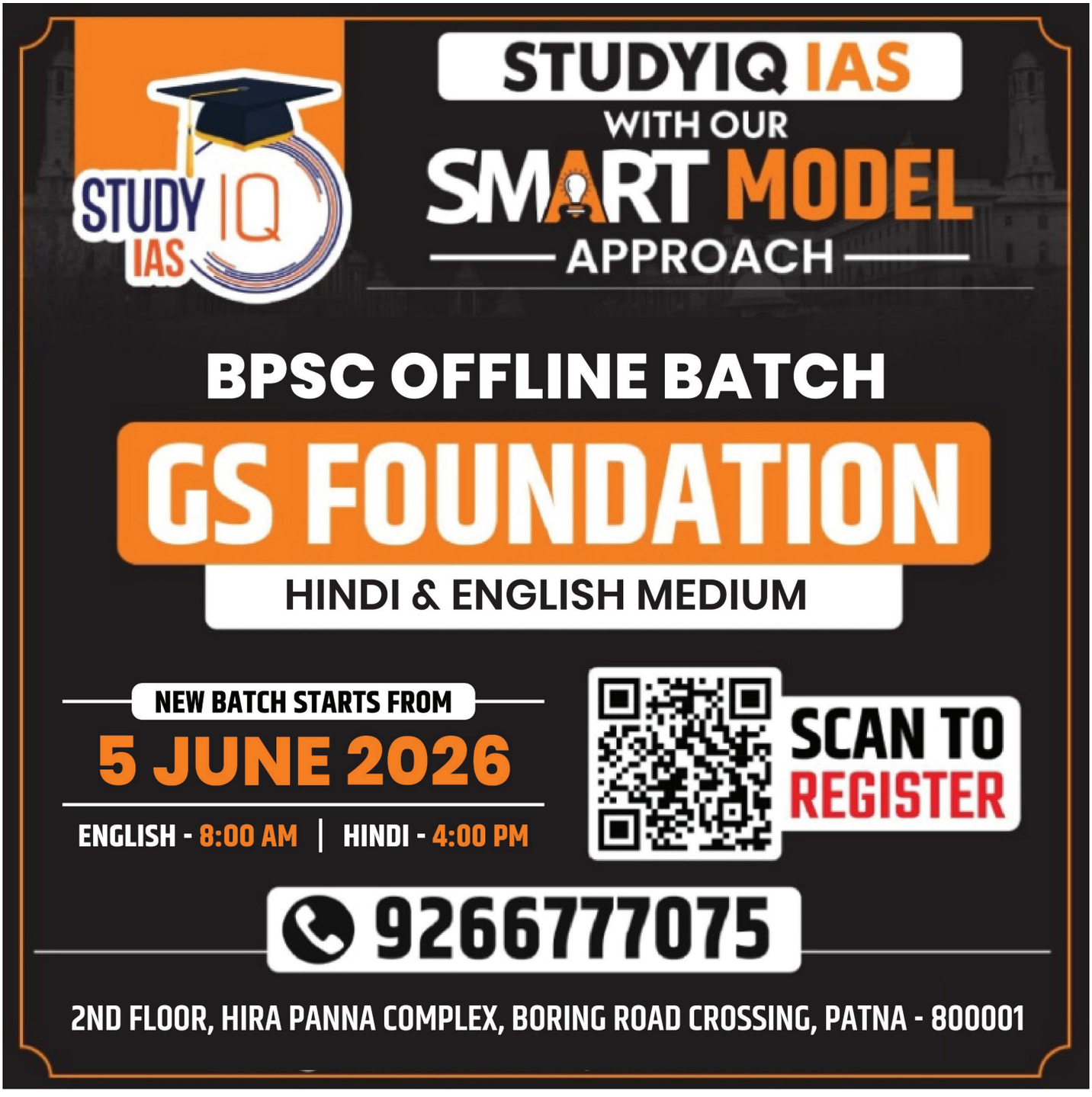

STUDY IQ IAS

GS FOUNDATION
UPSC / BPSC
WITH SMART MODEL

BOOK YOUR FREE
MENTORSHIP SESSION

SCAN TO REGISTER

9266777075

2nd Floor, Hira Panna Complex, Boring Road Crossing, Patna - 800001

BPSC ONLINE BATCHES

अभ्युदय
BPSC (Prelims + Mains)
LIVE Foundation Batch हिंदी माध्यम
Admissions Closing On 15th June 2026
GOLD : ₹9,999/-
PLATINUM : ₹15,999/-

BIHAR PSC
आरम्भ
PRE+MAINS+INTERVIEW
LIVE FOUNDATION JUNE BATCH
Batch Starting On 8th June 2026
GOLD : ₹ 9,999/-
PLATINUM : ₹14,999/-

72ND BPSC
Prelims Live
Course 2026
Batch Just Started
GOLD : ₹6,399/-
PLATINUM : ₹11,199/-

USE CODE STUDY50
FOR ANY QUERIES CALL : 92-8999-6924